RNI No. : UPBIL/25/A0683 | www.vicharsetu.com | वर्ष-01 | अंक-05 | जुलाई-अगस्त 2026 | पृष्ठ संख्या-44

विचार सेतु

विचार से विश्वास तक

प्रयागराज से प्रकाशित

मूल्य ₹ 40

आस्था पर सेंध

श्री राम मंदिर दान चोरी मामला

राम केवल अस्था नहीं, राष्ट्र की आत्मा हैं

मंदिरों की सुरक्षाः अस्था की अनिवार्यता

दान नहीं, यह जन विश्वास है

आध्यात्मिक स्थलों पर साइबर खतरे

विसे
विचार से विश्वास तक

विचार सेतु

विचार से विश्वास तक रहेगा
प्रयागराज से प्रकाशित

राज, समाज, साहित्य, संस्कृति, कला एवं पर्यटन की राष्ट्रीय पत्रिका/समाचार पत्र

आप भी अपना विज्ञापन देकर कारोबार को बढ़ाएं

हर तस्वीर एक कहानी बताती है और हम अपनी पत्रिका से लाखों को बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जो बिना किसी भेदभाव के वास्तविक दुनिया और लोगों के बारे में सच्चाई बताती है।

हमारे साथ विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को दें नई उड़ान

विज्ञापन की दरें :-

बैक कवर-21,000/-	फुल पेज- 11,000/-
फ्रंट इनर कवर-15,000/-	हाफ पेज- 6,000/-
बैक इनर कवर-15,000/-	क्वाटर पेज-3,000/-

विचार सेतु
विचार से विश्वास तक रहेगा
प्रयागराज से प्रकाशित

Follow us

संपादकीय कार्यालय : 11/2सी/1क्यू, भोला का पुरा,
प्रीतम नगर, धूमनगंज,
प्रयागराज -211011

Mob. No. 9598163216-7007044100
Website: www.vicharsetu.com
e-Mail: vicharsetu2024@gmail.com

अंदर

06

12 साल की मोदी सरकार

भारत की राजनीति में वर्ष 2014 एक ऐतिहासिक बदलाव का वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।

08

आस्था पर सेंध श्रीराम मंदिर :सुचिता,साख और संवैधानिक जवाबदेही

विश्व के अनेक देशों में बसे सनातन धर्मावलंबियों ने भी इस निर्माण को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक गौरव...

12

बदलती जलवायु, पर्यावरणीय चेतना और आपदा-प्रबंधन के युग में भूकंप-सुनामी

पृथ्वी एक जीवंत, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील ग्रह है। इसकी सतह पर दिखाई देने वाली स्थिरता वास्तव में एक आभासी...

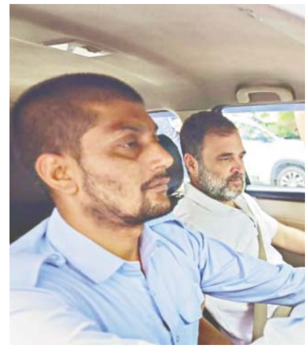

16

राहुल गांधी-टैक्सी चालक संवाद 'गिग वर्कर्स' की हकीकत

रक्षाबंधन, 19 अगस्त 2024। दिल्ली की सड़कों पर जब बाकी नेता काफिलों में चल रहे थे, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल...

42

सलमान खान का नाम लेने पर ऐश्वर्या ने करण जौहर को दिखाई आंख

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशन बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिलेशंस में से है। ब्रेक अप के बाद दोनों कभी एक दूसरे के साथ फिल्म में दिखाई दिए और ना तो कभी किसी इवेंट...

18

भाजपा का नया उप्र में संगठनः क्या जातीय संतुलन से 2027...

उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नया संगठन घोषित किया है।

26

नीट पेपर लीकः सपनों पर सवाल, भरोसे का संकट

मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का एकमात्र राष्ट्रीय माध्यम मानी जाने वाली नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण अब शिक्षा व्यवस्था के...

विचार सेतु

वर्ष-01, अंक-05, जुलाई-अगस्त 2026

RNI No. : UPBIL/25/A0683
पृष्ठ संख्या-44, मूल्य- ₹ 40

सम्पादक : रेखा तिवारी

प्रधान सम्पादक : प्रदीप तिवारी, एडवोकेट
कार्यकारी सम्पादक : संजय कुमार
समन्वय संपादक : शिवा शंकर पाण्डेय
प्रबंध संपादक : आलोक पाण्डेय

संरक्षक मण्डल
पदमश्री डॉ. सुनील जोगी, प्रेम जन्मेजय, रविनंदन सिंह, हर्ष वर्धन त्रिपाठी, डॉ. धनंजय चोपड़ा

राजनैतिक संवाददाता : भास्कर मिश्रा
सांस्कृतिक संवाददाता : राजेश ओझा

राज्य प्रतितिधि
उत्तर प्रदेश : भानुकर मिश्र,
बिहार : डॉ. चंद्रकांत भट्ट
मध्य प्रदेश : सुमित ओरछा
दिल्ली/एनसीआर : काशी शर्मा
पंजाब : विजय गर्ग
राजस्थान : गगन अग्रवाल
उत्तराखंड : ज्ञान प्रकाश पाण्डेय
हरियाणा : गजेन्द्र सिंह 'दहिया'
महाराष्ट्र : डॉ. मोतीलाल गुप्त 'आदित्य'
उड़ीसा : डॉ. रजनीकांत मिश्र
असम : त्रिदीप कलिता
त्रिपुरा : तनुज शाह
पश्चिम बंगाल : मानवेंद्र शर्मा

डिजाइन एवं प्रोडक्शन
एनएम मीडिया सॉल्यूशंस (9717177725)

विधिक सलाहकार
जयवर्धन त्रिपाठी, आदर्श पराशर
अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

छायाकार : संजय सागर, **अमित शर्मा**

पंजीकृत कार्यालय - 11/2सी/1क्यू, भोला का पुरा, प्रीतम नगर, धूमनगंज, प्रयागराज 211011
फोन: 9598163216,7007044100
9415189919
वेब : www.vicharsetu.com
ई-मेल : vicharsetu2024@gmail.com

स्वामी और प्रकाशक रेखा तिवारी द्वारा आइडियल ग्राफिक्स 48/136/2, पानदरीबा, शाहगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211003 से प्रकाशित।

संपादक-रेखा तिवारी*
मुद्रक : आइडियल ग्राफिक्स

इस पत्रिका के सभी पद अवैतनिक हैं

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

*इस चयन में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद प्रयागराज न्यायालय के अधीन होंगें।

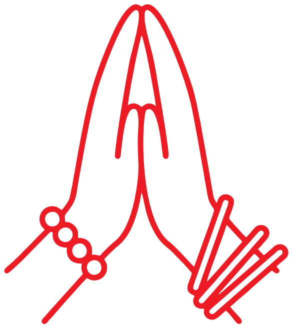

प्रिय पाठकों,

आज पत्रकारिता अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। सूचना की गति बढ़ी है, परंतु सत्य तक पहुँचना कठिन हुआ है। सोशल मीडिया के इस युग में अफवाहें भी तथ्यों की गति से दौड़ रहीं हैं। ऐसे समय में पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, विश्वसनीयता।

'विचार सेतु' का विश्वास है कि पत्रकारिता का धर्म किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि समाज को तथ्य, संदर्भ और विवेक प्रदान करना है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक सूचित होते हैं, पत्रकार निर्भीक होते हैं और संस्थाएँ जवाबदेह होती हैं।

हम जानते हैं कि हर पाठक हमारे हर निष्कर्ष से सहमत नहीं होगा, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारा आग्रह केवल इतना है कि असहमति तथ्यों पर आधारित हो, संवाद सम्मानपूर्ण हो और विमर्श राष्ट्रहित से प्रेरित हो।

'विचार सेतु' अपने नाम के अनुरूप विचारों का सेतु बनने के लिए प्रतिबद्ध है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच, पीढ़ियों के बीच और विचारधाराओं के बीच।

मैं इस अंक के सभी लेखकों, शोधकताओं, संवाददाताओं, स्तंभकारों, सहयोगियों, विज्ञापनदाताओं तथा अपने सम्मानित पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

आइए, हम ऐसा भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाएँ जहाँ आस्था सुरक्षित हो पर अंधविश्वास न हो, राजनीति सक्रिय हो पर समाज विभाजित न हो, विकास तेज हो पर प्रकृति उपेक्षित न हो, शिक्षा प्रतिस्पर्धी हो पर ईमानदारी से समझौता न हो और पत्रकारिता निर्भीक हो पर निष्पक्षता कभी न छोड़े।

इन्हीं भावनाओं के साथ 'विचार सेतु' द्विभाषी राष्ट्रीय पत्रिका का यह विशेषांक आपको समर्पित है। हमें विश्वास है कि यह अंक केवल पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि चर्चा, संवाद और सकारात्मक चिंतन का आधार बनेगा।

रेखा तिवारी

रेखा तिवारी
संपादक

विश्वास, विवेक और विमर्श का समय

पत्रकारिता का पहला दायित्व केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज के विवेक को जागृत करना है।

प्रिय पाठकों,

इतिहास के कुछ दौर ऐसे होते हैं, जब घटनाएँ सिर्फ घटनाएँ नहीं रहतीं, वे समाज की चेतना, लोकतंत्र की विश्वसनीयता और राष्ट्र की दिशा तय करने वाले सवाल के तौर पर उभर कर सामने आती हैं। आज हमारा देश ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा है। एक ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव, आत्मनिर्भरता की नई उड़ान, डिजिटल क्रांति, मजबूत होती अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत होता दिखाई देता है, तो दूसरी ओर व्यवस्था की पारदर्शिता, शिक्षा की निष्पक्षता, राजनीति की विश्वसनीयता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे प्रश्न भी उतनी ही तीव्रता से हमारे सामने उपस्थित हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर न तो केवल सरकारों के पास है, न विपक्ष के पास और न ही किसी एक विचारधारा के पास। उत्तर तभी संभव है जब समाज प्रश्न पूछने का साहस बनाए रखे, संस्थाएँ आत्ममंथन करती रहें और पत्रकारिता सत्ता तथा समाज दोनों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी बनी रहे। इसी विश्वास के साथ 'विचार सेतु' द्विभाषी राष्ट्रीय पत्रिका का जुलाईझअगस्त अंक आपके हाथों में है। हमारा उद्देश्य सनसनी पैदा करना नहीं, आरोप गढ़ना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर विमर्श को दिशा देना है। यही कारण है कि इस अंक की प्रत्येक आवरण कथा, विश्लेषण, रिपोर्ट और साहित्यिक प्रस्तुति एक साझा सूत्र से जुड़ी है, विश्वास की रक्षा और उत्तरदायित्व की स्थापना।

इस अंक की आवरण कथा ₹आस्था पर सेंध₹ केवल एक कथित वित्तीय अनियमितता की कहानी नहीं है। यह उस प्रश्न की पड़ताल है कि जिन संस्थाओं में करोड़ों लोगों की श्रद्धा बसती है, वहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का स्तर सबसे ऊँचा क्यों नहीं होना चाहिए? श्रीराम भारतीय जनमानस की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। इसलिए यदि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान प्रबंधन पर कोई प्रश्न उठता है, तो उसका समाधान भी तथ्यों, निष्पक्ष जांच और संस्थागत पारदर्शिता के माध्यम से ही होना चाहिए। आस्था को राजनीति का हथियार बनाने से भी बचना होगा और आस्था के नाम पर जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति से भी। इसी प्रकार नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण केवल एक परीक्षा का संकट नहीं है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है, जिस पर देश के लाखों युवाओं का भविष्य टिका है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यदि प्रतिभा का मार्ग ईमानदारी से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और प्रश्नपत्र माफियाओं से होकर गुजरेगा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी को होगा। शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश की राजनीति सदैव से राष्ट्रीय राजनीति की धुरी रही है। इस अंक में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश संगठन का विश्लेषण केवल पदाधिकारियों की सूची नहीं, बल्कि उसके सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संकेतों को समझने का प्रयास है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की नई संरचना यह बताती है कि राजनीति केवल चुनाव नहीं, बल्कि समाज के बदलते समीकरणों का दर्पण भी है।

विशेष रूप से प्रयागराज के बहाने पूर्वांचल को साधने की रणनीति इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श है। प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक परंपरा और राजनीतिक प्रभाव उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्वाभाविक केंद्र बनाते हैं। आज लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल इस भूभाग को अपनी रणनीति के केंद्र में रख रहा है। प्रश्न यह नहीं कि कौन किसे साध रहा है, प्रश्न यह है कि क्या इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्षेत्र के विकास, रोजगार, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक समरसता के रूप में सामने आएगा?

राष्ट्र की सीमाएँ केवल सैन्य शक्ति से सुरक्षित नहीं होतीं, वे नागरिकों के विश्वास, लोकतंत्र की मजबूती और विकास की क्षमता से भी सुरक्षित होती हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के प्रति समर्थन की उभरती आवाजों का विश्लेषण इसी व्यापक संदर्भ में किया गया है। यह विषय भावनात्मक होने के साथ-साथ रणनीतिक भी है। भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक शक्ति का प्रभाव पड़ोसी क्षेत्रों की सोच पर भी दिखाई देता है। इस विषय को हमने संतुलित और तथ्याधारित दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारह वर्षों के नेतृत्व पर आधारित विशेष लेख किसी प्रशस्ति या आलोचना का दस्तावेज नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यांकन का प्रयास है। किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके नारों से नहीं, बल्कि उसकी नीतियों व उनके परिणामों से होना चाहिए। अधोसंरचना, डिजिटल परिवर्तन, विदेश नीति, सामाजिक योजनाएं, आर्थिक सुधार व प्रशासनिक निर्णय,इन सभी आयामों का विश्लेषण आवश्यक है। लोकतंत्र में उपलब्धियों को स्वीकार करना और कमियों की ओर संकेत करना,दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।

इसी प्रकार राहुल गांधी और टैक्सी चालक के संवाद को हमने केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा। लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति जितनी मजबूत होगी, शासन उतना ही जनोन्मुख होगा। विचारों का आदान-प्रदान लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता और विपक्ष—दोनों का दायित्व है कि वे जनता से संवाद बनाए रखें और जनता का दायित्व है कि वह तथ्यों के आधार पर निर्णय ले। किन्तु समाज केवल राजनीति से नहीं चलता। उसकी आत्मा साहित्य, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं में बसती है। यही कारण है कि इस अंक में प्रकाशित लघुकथा ₹धर्म पिता₹ मानवीय रिश्तों की गरिमा, त्याग और अपनत्व का भावपूर्ण दस्तावेज है। साहित्य मनुष्य को केवल पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि महसूस करना भी सिखाता है।

इसी प्रकार बदलती जलवायु, पर्यावरणीय चेतना, भूकंप और सुनामी जैसे विषयों पर प्रकाशित लेख हमें यह स्मरण कराते हैं कि प्रकृति के साथ संघर्ष में मानव कभी विजेता नहीं हो सकता। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही भविष्य का वास्तविक विकास मॉडल होगा। आने वाली पीढ़ियों को केवल आर्थिक संपन्नता नहीं, बल्कि सुरक्षित धरती भी विरासत में देना हमारी साझा जिम्मेदारी है। मनोरंजन जगत की हलचलें भी समाज की बदलती संस्कृति का दर्पण होती हैं। इसलिए फिल्म जगत की चुनिंदा घटनाओं को भी इस अंक में स्थान दिया गया है, क्योंकि संस्कृति और समाज का संबंध अविभाज्य है।

संजय कुमार
कार्यकारी संपादक

12 साल की मोदी सरकार

फैसलों, विकास योजनाओं और राजनीतिक बदलावों का एक दशक से अधिक का सफर

धीरज कश्यप

भारत की राजनीति में वर्ष 2014 एक ऐतिहासिक बदलाव का वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद 2019 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और 2024 में तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को समर्थक विकास, राष्ट्रहित और बड़े नीतिगत फैसलों का दौर बताते हैं, जबकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना करता रहा है। इस अवधि में केंद्र सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए, जिनका प्रभाव देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर देखने को मिला।

मोदी सरकार के प्रमुख ऐतिहासिक निर्णय

मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना प्रमुख रहा। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को समाप्त किया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण और समान कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया, वहीं विपक्ष ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रहा। लंबे समय से चले आ रहे राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भाजपा इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक क्षण मानती है। आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया। इसका उद्देश्य देश में अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक समान कर व्यवस्था बनाना था। सरकार ने इसे 'एक देश, एक कर' की दिशा में बड़ा आर्थिक सुधार बताया।

डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

जैसी योजनाओं ने देश में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया। करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था को बढ़ावा मिला। यूपीआई व डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल भुगतान देशों में शामिल किया। रक्षा और उद्योग क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। सरकार ने रक्षा उपकरणों के घरेलू निर्माण और रक्षा निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक चलाया। इसके साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने राहत पहुंचाने का प्रयास किया।

भाजपा का राजनीतिक विस्तार और राज्यों में सरकारें

12 वर्षों के दौरान भाजपा देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों में शामिल हुई है। भाजपा ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई और कई राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोग से सत्ता में भागीदारी की। उप्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा और ओडिशा जैसे राज्यों में भाजपा ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई है। हालांकि राज्यों में सरकारों की संख्या चुनाव परिणामों के अनुसार बदलती रहती है।

आरएसएस की भूमिका और भाजपा का संगठन विस्तार

भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। वर्ष 1925 में स्थापित आरएसएस स्वयं को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा संगठन बताता है। भाजपा के कई बड़े नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं और दोनों संगठनों के बीच वैचारिक संबंध माना जाता है। भाजपा के चुनावी विस्तार में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक पहुंच को महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनावों के दौरान आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक सामाजिक संपर्क, जनजागरण और संगठनात्मक समन्वय जैसे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। आरएसएस का मजबूत नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों तक सामाजिक संपर्क बनाने में सहायक माना जाता है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान व सामाजिक एकता जैसे मुद्दों पर आरएसएस लंबे समय से काम करता रहा है, भाजपा ने अपने राजनीतिक अभियानों में राष्ट्र सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता दी है। आपातकाल के दौर में भी आरएसएस से जुड़े कार्यकताओं की भूमिका चर्चा में रही। इसके बाद संगठन का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। भाजपा के विस्तार में पार्टी कार्यकताओं के साथ-साथ वैचारिक संगठनों के सहयोग को भी राजनीतिक विश्लेषक महत्वपूर्ण मानते हैं।

कांग्रेस शासन व मोदी सरकार की तुलना

स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस सरकारों ने देश में बड़े संस्थानों की स्थापना, हरित क्रांति, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विकास व आर्थिक उदारीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। मोदी सरकार के पिछले दशक में सड़क निर्माण, रेलवे आधुनिकीकरण, डिजिटल क्रांति,बिजली कनेक्शन, शौचालय निर्माण, बैंकिंग सुविधा व गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी आई है। आलोचक रोजगार, महंगाई, किसानों की आय व सामाजिक मुद्दों पर सरकार से अधिक काम की अपेक्षा रखते हैं। किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसकी उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों के आधार पर किया जाता है।

कांग्रेस सरकारों से जुड़े प्रमुख विवाद और घोटाले

कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों के दौरान कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, जिन पर देश में राजनीतिक बहस हुई। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दूरसंचार लाइसेंस आवंटन को लेकर आरोप लगे। हालांकि बाद में विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया और मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा। कोयला आवंटन मामले में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर सवाल उठे व कई मामलों में जांच हुई। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े खर्च और व्यवस्थाओं को लेकर भी विवाद सामने आया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रिश्वत के आरोपों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया।

कांग्रेस परिवार से जुड़े कानूनी मामले

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) ने जांच की है। कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि जांच एजेंसियां इसे वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा मामला बताती हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष भारतीय राजनीति में बड़े बदलावों का समय रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, जीएसटी, डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व गरीब कल्याण योजनाएं सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रही हैं।

कांग्रेस के लंबे शासनकाल ने भी भारत के संस्थागत विकास और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार का मूल्यांकन जनता के अनुभव, विकास कार्यों और नीतियों के प्रभाव के आधार पर होता है। आने वाले समय में रोजगार, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामाजिक मुद्दे भारतीय राजनीति के प्रमुख विषय बने रहेंगे।

(लेखक : स्वतंत्र स्तंभकार एवं राजनीतिक विशेषज्ञ)

आस्था पर सेंध

श्रीराम मंदिर

सुचिता, साख और सवैधानिक जवाबदेही

अजीत सिंह

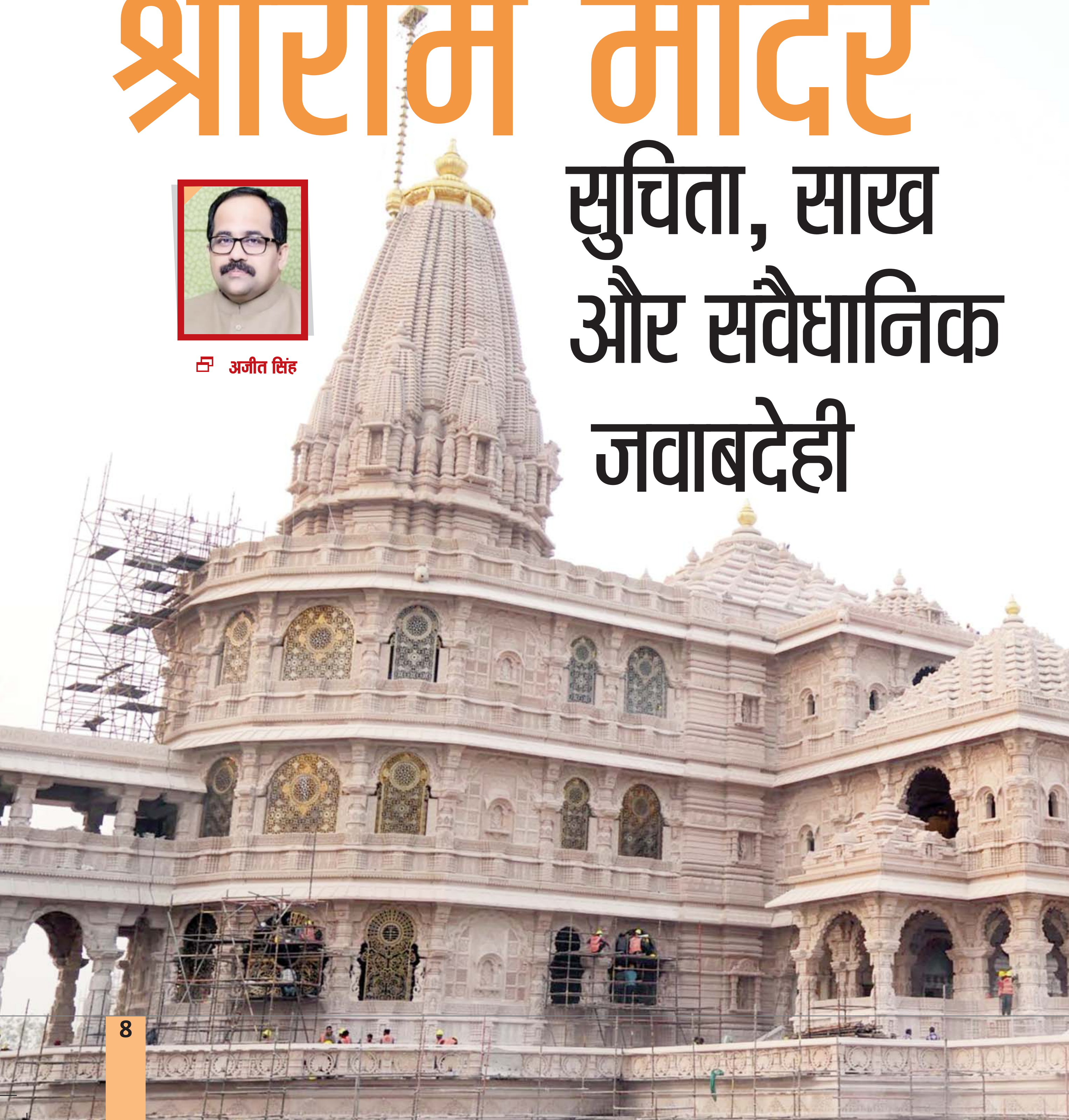

श्रीराम मंदिर और पारदर्शिता की अनिवार्यताः आस्था का सम्मान, उत्तरदायित्व की कसौटी

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं था; यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की सदियों पुरानी आस्था का मूर्त रूप है। इस मंदिर के निर्माण में देश-विदेश के असंख्य रामभक्तों ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम की कमाई का अंश समर्पित किया। किसी ने सौ रुपये दिए, किसी ने लाखों का दान किया, तो किसी ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर योगदान दिया। इन सभी दानदाताओं की एक ही भावना थी—भगवान श्रीराम के चरणों में समर्पण।

यही कारण है कि यदि मंदिर निर्माण अथवा चंदे के उपयोग को लेकर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शिता या हेराफेरी के आरोप सामने आते हैं, तो यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं रह जाता। यह करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की नैतिक विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है। आस्था पर संदेह की छाया पड़ना किसी भी धार्मिक समाज के लिए अत्यंत पीड़ादायक स्थिति होती है।

धर्म का वास्तविक आधार केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि सत्य, नैतिकता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व है। भारतीय संस्कृति ने सदैव यह शिक्षा दी है कि धर्म वहीं है जहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य नहीं, वहाँ धर्म का अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाता है। मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम का संपूर्ण जीवन न्याय, पारदर्शिता, वचनबद्धता और लोककल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसे में उनके नाम पर संचालित किसी भी कार्य से समाज की अपेक्षाएँ सामान्य संस्थाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होना स्वाभाविक है।

> विश्व के अनेक देशों में बसे सनातन धर्मावलंबियों ने भी इस निर्माण को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक गौरव से जोड़कर देखा है। इसलिए मंदिर से जुड़ी प्रत्येक घटना का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। अपारदर्शिता की आशंका लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे केवल एक संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होती, बल्कि सनातन परंपरा की छवि पर भी अनावश्यक प्रश्न उठते हैं। ऐसे प्रश्नों का सबसे प्रभावी उत्तर भावनात्मक तर्क नहीं, बल्कि पूर्ण पारदर्शिता और सत्यनिष्ठ प्रशासन ही हो सकता है।

आज आवश्यकता आरोपों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की है। लोकतंत्र में किसी भी आरोप को बिना जांच के अंतिम सत्य मान लेना न्यायसंगत नहीं है। दूसरी ओर, यदि गंभीर आरोपों की अनदेखी कर दी जाए या उन्हें केवल विरोध का षड्यंत्र कहकर टाल दिया जाए, तो इससे भी जनविश्वास कमजोर होता है। अतः दोनों अतियों से बचना आवश्यक है।

यह विचारणीय है कि किसी भी बड़े धार्मिक ट्रस्ट का गठन स्पष्ट नियमों, वित्तीय अनुशासन, मानक संचालन प्रक्रिया

(एसओपी), लेखा-परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र के साथ किया जाता है। प्रत्येक पदाधिकारी की भूमिका और जवाबदेही भी निर्धारित होती है।

यदि इन सबके बावजूद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो केवल आरोपित व्यक्तियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता की भी समीक्षा होना स्वाभाविक है। यदि उत्तरदायित्व तय नहीं होगा, तो संस्थागत सुधार की प्रक्रिया भी अधूरी रह जाएगी।

यह भी ध्यान रखना होगा कि श्रीराम मंदिर केवल भारत का विषय नहीं है। विश्व के अनेक देशों में बसे सनातन धर्मावलंबियों ने भी इस निर्माण को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक गौरव से जोड़कर देखा है। इसलिए मंदिर से जुड़ी प्रत्येक घटना का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। यदि किसी प्रकार की अपारदर्शिता की आशंका लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे केवल एक संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होती, बल्कि सनातन परंपरा की छवि पर भी अनावश्यक प्रश्न उठते हैं। ऐसे प्रश्नों का सबसे प्रभावी उत्तर भावनात्मक तर्क नहीं, बल्कि पूर्ण पारदर्शिता और सत्यनिष्ठ प्रशासन ही हो सकता है।

यदि आरोप निराधार हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य सामने आना चाहिए, जिससे भ्रम समाप्त हो और श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता सिद्ध होती है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्था की गरिमा व्यक्तियों से बड़ी होती है। व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन संस्था और उससे जुड़ी आस्था सदैव सर्वोपरि रहती है।

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा हमें यह सिखाता है कि जवाबदेही किसी भी संस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। पारदर्शिता से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास ही किसी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए समय की मांग है कि श्रीराम मंदिर से जुड़े प्रत्येक वित्तीय और प्रशासनिक पहलू को इतना स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए कि भविष्य में किसी प्रकार के संशय की कोई गुंजाइश ही न रहे।

आज आवश्यकता किसी पक्ष या विपक्ष

की नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने की है। क्योंकि सत्य ही श्रीराम का मार्ग है, न्याय ही उनका संदेश है और मयार्दा ही उनकी पहचान है। यदि हम वास्तव में श्रीराम के आदर्शों का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनके मंदिर से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था भी सत्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय के सर्वोच्च मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।

1.आस्था से खिलवाड़ सनातन होगा कमजोर

2.राम मंदिर में चंदा चोरी सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व सनातन प्रेमियों को लगा झटका

3.राम मंदिर चंदा चोरी पर निष्पक्ष जाँच से ही लौटेगी आस्था की पूंजी

श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आत्मा का केंद्र है। इसकी पवित्रता केवल भव्य शिखरों से नहीं, बल्कि उससे जुड़े प्रत्येक निर्णय की ईमानदारी और पारदर्शिता से सुरक्षित रहेगी। यही रामभक्ति का वास्तविक सम्मान है, यही सनातन की गरिमा है और यही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सर्वोत्तम उदाहरण भी।

बदलती जलवायु, पर्यावरणीय चेतना और आपदा-प्रबंधन के युग में भूकंप-सुनामी

अमल मिश्र

पृथ्वी एक जीवंत, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील ग्रह है। इसकी सतह पर दिखाई देने वाली स्थिरता वास्तव में एक आभासी स्थिरता है। पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का संचय और विसर्जन लगातार होता रहता है, महासागर अपनी गहराइयों में अनेक भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समेटे रहते हैं, वायुमंडल में निरंतर हलचल चलती रहती है और धरातल समय के साथ अपना स्वरूप बदलता रहता है। पर्वतों का निर्माण, नदियों का मार्ग परिवर्तन, ज्वालामुखियों का विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी घटनाएं इसी गतिशील पृथ्वी की अभिव्यक्तियां हैं। मानव सभ्यता का विकास इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच हुआ है, इसलिए इन घटनाओं का अध्ययन केवल भूगोल का विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व, पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक सुरक्षा और सतत विकास का भी प्रश्न है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, समुद्र-स्तर वृद्धि, पर्यावरणीय क्षरण और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भूकंप और सुनामी जैसे विषय केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं रह गए हैं। वे मानव समाज की तैयारी, सरकारी नीतियों, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता से सीधे जुड़ गए हैं।

यद्यपि भूकंप और सुनामी का प्रत्यक्ष संबंध पृथ्वी की आंतरिक भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है, फिर भी इनके प्रभावों की तीव्रता आज बदलती जलवायु और असंतुलित विकास के कारण अधिक जटिल होती जा रही है।

जर्मन प्रकृतिवादी एवं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट (1769-1859) का मानना था कि प्रकृति एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है, जहाँ किसी एक घटक में परिवर्तन अन्य अनेक घटकों को प्रभावित करता है। आधुनिक पृथ्वी-प्रणाली विज्ञान भी इसी विचार की पुष्टि करता है। भूगोलवेत्ता यह मानते हैं कि पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जीवमंडल के बीच गहरा अंतसंबंध है। इसलिए जब समुद्र तल में कोई शक्तिशाली भूकंप आता है व सुनामी उत्पन्न होती है, तो उसका प्रभाव केवल तटीय भूभाग तक सीमित नहीं रहता; वह पर्यावरण, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना तक को प्रभावित करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रख्यात जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर (1880-1930) द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय विस्थापन

सिद्धांत और बाद में विकसित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी की सतह अनेक विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो निरंतर गतिशील हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का टकराव आज भी जारी है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में गिना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिकों और भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ऊर्जा का संचय निरंतर हो रहा है, इसलिए भविष्य में भी बड़े भूकंपों की संभावना बनी रहेगी। प्रसिद्ध कनाडाई भूभौतिकीविद जॉन तुजो विल्सन ने पृथ्वी को एक निरंतर परिवर्तित होती प्रणाली के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल दिया था। आज यह दृष्टिकोण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक जोखिमों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यद्यपि जलवायु परिवर्तन सीधे भूकंप उत्पन्न नहीं करता, किंतु ग्लेशियरों के तीव्र पिघलने, समुद्र-स्तर वृद्धि तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू-संतुलन में आने वाले परिवर्तनों के कारण कुछ क्षेत्रों में भूकंपीय संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। हिमालयी क्षेत्र में तेजी से पिघलते हिमनदों व बनने वाली हिमनदीय झीलों को लेकर वैज्ञानिक विशेष चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु वैज्ञानिक लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने से तटीय क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है। समुद्र-स्तर में वृद्धि के कारण यदि किसी तटीय क्षेत्र में सुनामी आती है तो उसका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो सकता है। समुद्र तटों पर अनियोजित शहरीकरण, मैंग्रोव वनों का विनाश और प्राकृतिक अवरोधों की कमी भी विनाश की तीव्रता बढ़ा देती है। भूकंप पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने का परिणाम है। जब चट्टानों पर लंबे समय तक तनाव बढ़ता रहता है उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है, तब वे टूट जाती हैं और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही तरंगें धरती को कंपित करती हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और भूकंपविज्ञानी चार्ल्स रिक्टर (1900-1985) द्वारा विकसित रिक्टर पैमाना और आधुनिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल हमें इन घटनाओं की तीव्रता को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। किंतु आज वैज्ञानिकों का ध्यान केवल भूकंप की शक्ति मापने तक सीमित नहीं है; वे इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का भी व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। सुनामी इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। समुद्र तल में आने वाले शक्तिशाली भूकंप, ज्वालामुखीय विस्फोट या समुद्री भूस्खलन के कारण उत्पन्न विशाल तरंगें हजारों किलोमीटर दूर स्थित तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। भूगोलवेत्ताओं का मत है कि सुनामी पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के पारस्परिक संबंधों का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। समुद्र तल में उत्पन्न एक भू-वैज्ञानिक घटना कुछ ही घंटों में मानव बस्तियों, कृषि भूमि, बंदरगाहों, मत्स्य संसाधनों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित कर सकती है।

26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी और 2011 की जापान की तोहोकू सुनामी ने विश्व समुदाय को यह गहरी सीख दी कि प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध केवल वैज्ञानिक प्रगति और अत्याधुनिक तकनीक पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि समाज मानसिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयार न हो तो आधुनिकतम संसाधन भी व्यापक जनहानि और विनाश को पूरी तरह रोक नहीं सकते। विशेष रूप से जापान के अनुभव ने यह सिद्ध किया कि आपदा-प्रबंधन की सफलता केवल चेतावनी प्रणालियों या तकनीकी उपकरणों पर निर्भर नहीं करती, नागरिकों के अनुशासन, सामुदायिक सहभागिता, नियमित प्रशिक्षण

और संकट की घड़ी में त्वरित एवं संगठित प्रतिक्रिया पर भी समान रूप से निर्भर करती है। जापानी भूगोलवेत्ताओं और आपदा विशेषज्ञों ने इस निष्कर्ष पर बल दिया कि आपदा से सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन वह समाज है जो संभावित जोखिमों को समझता हो, उनके प्रति सजग हो और समय-समय पर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को तैयार रखता हो। आज भूकंप और सुनामी को केवल भूगर्भीय या प्राकृतिक घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय चुनौती के रूप में भी समझा जाता है।

किसी बड़े भूकंप अथवा सुनामी का प्रभाव केवल भवनों और अवसंरचनाओं के विनाश तक सीमित नहीं रहता। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री जीव-जंतु, मत्स्य संसाधन तथा अन्य जैविक तंत्र गंभीर क्षति का सामना कर सकते हैं। समुद्री जल के कृषि भूमि में प्रवेश करने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और अनेक क्षेत्रों में वर्षों तक खेती करना कठिन हो जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनेक बार लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे विस्थापन, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि वर्तमान समय में तटीय क्षेत्रों में तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय क्षरण ने आपदा जोखिम को और बढ़ा दिया है। जिन तटीय क्षेत्रों में कभी मैंग्रोव वन प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते थे, वहाँ आज अनेक स्थानों पर औद्योगिक परियोजनाएं, बंदरगाह, पर्यटन अवसंरचनाएँ और आवासीय बस्तियाँ विकसित हो चुकी हैं। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवरोध कमजोर हुए हैं और समुद्री आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में हो रही क्रमिक वृद्धि भी इस चुनौती को और गंभीर बना रही है। यद्यपि सुनामी का प्रत्यक्ष कारण समुद्र तल में होने वाली भूगर्भीय गतिविधियाँ हैं, किंतु बढ़ता समुद्र-स्तर तटीय क्षेत्रों में उसके प्रभाव को अधिक विनाशकारी बना सकता है। इन आपदाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु प्रायः उपेक्षित पक्ष मानव मन और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव है। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के बाद प्रभावित समुदायों में भय, तनाव, अवसाद, असुरक्षा, अनिद्रा और मानसिक आघात जैसी समस्याएँ लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। विशेष रूप से वे बच्चे, महिलाएँ और वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपने परिजनों, घरों अथवा आजीविका को खोया हो, मानसिक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए आधुनिक आपदा-प्रबंधन में केवल भौतिक पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि मनोसामाजिक पुनर्वास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी समुदाय का वास्तविक पुनर्वास तब माना जाना चाहिए जब उसके लोग पुनः सामान्य जीवन, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता प्राप्त कर लें।

प्रख्यात अमेरिकी वैज्ञानिक, पर्यावरण चिंतक, इतिहासकार और भूगोलवेत्ता जेरेड डायमंड (1937) का मत है कि किसी समाज की वास्तविक शक्ति उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि संकटों का सामना करने की उसकी सामूहिक क्षमता से निर्धारित होती है। यह विचार आज वैश्विक आपदा-प्रबंधन नीतियों का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। आधुनिक दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि प्राकृतिक आपदाओं को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, किंतु वैज्ञानिक योजना, पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से उनके प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी कारण आज आपदा-प्रबंधन की अवधारणा राहत और पुनर्वास की सीमाओं से आगे बढ़कर जोखिम न्यूनीकरण, आपदा-पूर्व तैयारी और दीर्घकालिक लचीलापन विकसित करने पर केंद्रित हो गई है।

भारत ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2004 की सुनामी के अनुभव के बाद देश में आपदा-पूर्व चेतावनी और निगरानी प्रणालियों को अत्यधिक सुदृढ़ बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली आज हिंद महासागर क्षेत्र की प्रमुख प्रणालियों में गिनी जाती है। यह समुद्र तल की गतिविधियों, भूकंपीय संकेतों और समुद्री स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निरंतर निगरानी करके संभावित खतरे की सूचना समय रहते प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र तथा विभिन्न राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर एक समन्वित व्यवस्था के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, पूर्व चेतावनी, जन-जागरूकता और आपदा प्रतिक्रिया के कार्यों का संचालन कर रहे हैं।

तटीय राज्यों में नियमित आपदा अभ्यास, निकासी मार्गों का निर्धारण, सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण, विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम तथा स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण अब आपदा-प्रबंधन की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। अनेक स्थानों पर मछुआरों, तटीय निवासियों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को एकीकृत कर सामुदायिक आधारित आपदा-प्रबंधन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। भूगोलवेत्ताओं और आपदा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में आपदा से सुरक्षा का सबसे प्रभावी मार्ग वही होगा जिसमें विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता और जनसहभागिता एक-दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें।

यही समन्वित दृष्टिकोण मानव समाज को अधिक सुरक्षित, सक्षम और आपदा-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में सार्थक आधार प्रदान कर सकता है।सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में आपदा शिक्षा, स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी तथा नागरिकों की जागरूकता आपदा जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जापान, इंडोनेशिया और भारत के अनेक क्षेत्रों में सामुदायिक चेतना ने हजारों लोगों के जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यावरण संरक्षण भी आपदा न्यूनीकरण का एक प्रभावी माध्यम है।

तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, प्रवाल भित्तियों का संवर्धन तथा प्राकृतिक तटीय अवरोधों को सुरक्षित रखना सुनामी और समुद्री तूफानों के प्रभाव को कम कर सकता है। अनेक भूगोलवेत्ताओं और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल जैव विविधता की रक्षा का विषय नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा का भी प्रश्न है।

मानव चेतना के स्तर पर भी इन घटनाओं का विशेष महत्व है। भूकंप और सुनामी हमें यह स्मरण कराते हैं कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण का विचार एक भ्रम है। विज्ञान और तकनीक हमें जोखिम कम करने में सहायता दे सकते हैं, किंतु प्रकृति के साथ संतुलित सह-अस्तित्व ही दीर्घकालिक सुरक्षा का आधार बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और आपदा-जोखिम को विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया जाए। वास्तव में भूकंप व सुनामी केवल भू-वैज्ञानिक घटनाएं नहीं हैं; वे मानव समाज के लिए सीख, चेतावनी व आत्ममंथन का अवसर भी हैं। बदलती जलवायु, बढ़ते पर्यावरणीय संकट और तीव्र शहरीकरण के इस युग में वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, सामाजिक सहभागिता, प्रभावी सरकारी नीतियां व जागरूक नागरिकता ही एक सुरक्षित, सुदृढ़ और सतत भविष्य का आधार बन सकती हैं। प्रकृति को जीतना संभव नहीं है, किंतु उसे समझकर, उसका सम्मान करते हुए उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके हम एक अधिक सुरक्षित व संतुलित सभ्यता का निर्माण अवश्य कर सकते हैं।

(लेखक :एक स्वतंत्र स्तंभकार एवं पर्यावरणविद्)

राहुल गांधी-टैक्सी चालक संवाद
'गिग वर्कर्स' की हकीकत

आलोक पांडेय

रक्षाबंधन, 19 अगस्त 2024। दिल्ली की सड़कों पर जब बाकी नेता काफिलों में चल रहे थे, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अचानक उबर कैब बुक की। ड्राइवर सीट पर थे एटा के सुनील उपाध्याय। मंजिल सिर्फ कुछ किलोमीटर, पर मकसद था लाखों गिग वर्कर्स का दर्द समझना।

कैब में हुई 'मन की बात'

राहुल ने सुनील से पूछा- 'कमाई कितनी हो जाती है?'

जवाब आया- '3 साल से ऐसा कोई दिन नहीं जब 5000 रुपए कमा पाया हूं। जो कमाते हैं, सब खर्च हो जाता है। बच्चों की फीस, घर का खर्च। कभी बच्चों को घुमाने ले जाने के पैसे ही नहीं बचते'।

सुनील ने दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के कामों को याद किया। बोले- 'दिल्ली के सारे फ्लाई ओवर, सारे काम उन्हीं की सरकार में हुए थे'।

राहुल ने राजस्थान की गिग वर्कर्स योजना का जिक्र किया जो अशोक गहलोत सरकार ने लागू की थी। सुनील ने

कहा- 'बहुत बढ़िया है'।

ड्राइवर के घर लंच, परिवार से मुलाकात

सफर खत्म नहीं हुआ। राहुल सुनील के घर गए, पत्नी-बच्चों से मिले, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। बच्चों को गिफ्ट भी दिए। लंच के दौरान भी सवाल वही-'पेंशन है? बीमा है? छुट्टी मिलती है?'जवाब था-'कुछ नहीं सर'।

राहुल का ट्वीटः 'हैंड टू माउथ इनकम'

बाद में राहुल ने पर वीडियो पोस्ट कर लिखाः 'आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम - ये है भारत के गिग वर्कर की व्यथा! 'हैंड टू माउथ इनकम' में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है। न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार'।

उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गिग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाएंगी और INDIA गठबंधन इसे देशभर में लागू करवाएगा।

पहले भी निकले थे सड़क पर

ये पहली बार नहीं है। मई 2023 में राहुल दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रक में गए थे। ड्राइवरों ने बताया था- '10 हजार सैलरी, 12-24 घंटे काम, कोई बीमा नहीं, माल चोरी हो तो ड्राइवर जेल जाता है'।

नवंबर 2023 में तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स और गिग वर्कर्स से मिले थे। वाराणसी में 2014 में रिक्शा चालकों से कहा था-'आपकी तकलीफ समझने के लिए मैं एक दिन रिक्शा चलाने को तैयार हूं'।

संवाद का मकसद क्या?

कांग्रेस का कहना है कि राहुल 'देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियों को समझना चाहते हैं₹। विरोधी इसे 'इवेंट' कहते हैं।

पर सुनील उपाध्याय जैसे लाखों ड्राइवरों के लिए ये मुलाकात शायद पहली बार थी जब किसी बड़े नेता ने उनके घर बैठकर रोटी खाई और पूछा- 'आप कैसे हैं?'

भारत में 90 लाख ट्रक चालक और करोड़ों कैब-डिलीवरी वर्कर्स हैं। इनके पास न पीएफ है, न पेंशन, न छुट्टी। राहुल का ये संवाद इसी 'अदृश्य भारत' को सामने लाने की कोशिश है। ⓘ

भाजपा का नया उप्र में संगठन

क्या जातीय संतुलन से 2027 का चुनावी समीकरण साध पाएगी पार्टी?

मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में सवर्ण, ओबीसी, दलित और महिला प्रतिनिधित्व का संतुलन दिखा

लेकिन क्या यह सामाजिक इंजीनियरिंग वोटों में बदल पाएगी?

भास्कर मिश्र

उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नया संगठन घोषित किया है। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री,19 प्रदेश मंत्री,6 क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने गठन में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने का स्पष्ट प्रयास किया है।

शीर्ष नेतृत्व का संदेश

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और 2027 की चुनावी तैयारी को गति देना है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की भूमिका भी संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व का फोकस स्पष्ट रूप से सामाजिक प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रबंधन पर है।

प्रमुख पदाधिकारी और उनका राजनीतिक संदेश

प्रदेश उपाध्यक्षः प्रमुख नियुक्तियों में सुरेश राणा, नीरज सिंह (राजनाथ सिंह के पुत्र), पूजा पाल, प्रियंका रावत,अर्चना मिश्रा, सत्यपाल सैनी,देवेश कोरी,सुरेश मौर्य, राजेश यादव, आलोक गुप्ता सहित 19 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इन नियुक्तियों में जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित-महिला प्रतिनिधित्व का

मिश्रण दिखाई देता है।

प्रदेश महामंत्रीः महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेन्द्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल व राजेश चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। यहां भी ब्राह्मण, लोध,कुर्मी, शाक्य व अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है।

क्षेत्रीय अध्यक्ष

पश्चिम-नवाब सिंह नागर
ब्रज-पूरन लाल लोधी
कानपुर-रामकिशोर साहू
अवध-अवधेश द्विवेदी
काशी-अशोक चौरसिया
गोरखपुर-विनोद राय

6 क्षेत्रों में अलग-अलग सामाजिक समूहों के नेताओं को जिम्मेदारी देकर भाजपा ने क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है।

जातीय समीकरण का विश्लेषण

ओबीसी पर सबसे बड़ा दांव

नए संगठन में लोधी, साहू, सैनी, मौर्य, पटेल, शाक्य, यादव, चौधरी, चौरसिया और अन्य पिछड़े वर्गों के नेताओं को पर्याप्त स्थान मिला है। भाजपा का संदेश स्पष्ट है कि गैर-यादव पिछड़ा वर्ग अभी भी उसकी चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत आधार रहेगा।

सवर्ण मतदाताओं को भी संतुलित प्रतिनिधित्व

ब्राह्मण समाज से अर्चना मिश्रा, अभिजात मिश्रा, अवधेश द्विवेदी जैसे चेहरे हैं, जबकि ठाकुर समाज से सुरेश राणा, रामप्रताप सिंह चौहान और नीरज सिंह जैसे नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इससे भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को भी आश्वस्त करना चाहती है।

दलित और महिला प्रतिनिधित्व

देवेश कोरी, पूजा पाल, प्रियंका रावत, गीता शाक्य और अन्य महिला नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्व देकर भाजपा ने दलित और महिला मतदाताओं तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है।

क्या भाजपा की रणनीति सफल होगी?

भाजपा ने संगठन में लगभग हर प्रमुख सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर विपक्ष के ‘सामाजिक न्याय’ के नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति को मजबूत कर रही है। ऐसे में भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की वास्तविक परीक्षा बूथ स्तर पर होगी।

यदि संगठन जनता के बीच सक्रिय रहता है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल होता है, तो यह संतुलन चुनावी लाभ में बदल सकता है। लेकिन यदि स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई और टिकट वितरण में नाराजगी जैसे मुद्दे हावी रहे, तो केवल संगठनात्मक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होगा।

उप्र भाजपा का नया संगठन केवल पदाधिकारियों की सूची नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का सामाजिक व राजनीतिक खाका है। पार्टी ने ओबीसी, सवर्ण, दलित, महिलाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अब असली चुनौती इस प्रतिनिधित्व को वोटों में बदलने की है।

उत्तर प्रदेश का मतदाता केवल जातीय पहचान नहीं, बल्कि नेतृत्व, विकास, स्थानीय

मुद्दों व संगठन की सक्रियता के आधार पर भी निर्णय करेगा। इसलिए यह नया संगठन भाजपा के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। यह विश्लेषण उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है और राजनीतिक दृष्टि से संतुलित रखा गया है

एक तीर से दो निशाना

युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा के हाथ, युवाओं को साधने की नई रणनीति
उत्तर प्रदेश भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा को सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण एवं युवा मतदाता पार्टी की रणनीति के केंद्र में रहेगा। प्रतापगढ़ के मूल निवासी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे रोहित मिश्रा लंबे समय तक विद्यार्थी राजनीति और संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे पहले भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

रोहित मिश्रा की नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि भाजपा के उस अभियान का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और डिजिटल माध्यम से जुड़े युवा वर्ग तक पार्टी की पहुंच मजबूत करने की योजना है।

> उप्र भाजपा का नया संगठन केवल पदाधिकारियों की सूची नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का सामाजिक व राजनीतिक खाका है। पार्टी ने ओबीसी, सवर्ण, दलित, महिलाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अब असली चुनौती इस प्रतिनिधित्व को वोटों में बदलने की है। उत्तर प्रदेश का मतदाता केवल जातीय पहचान नहीं, बल्कि नेतृत्व, विकास, स्थानीय मुद्दों व संगठन की सक्रियता के आधार पर भी निर्णय करेगा।

राजनीतिक दृष्टि से प्रयागराज और पूर्वांचल में छात्र राजनीति का विशेष प्रभाव रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले अनेक नेता प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि वाले रोहित मिश्रा को प्रदेश युवा मोर्चा की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने संगठन को युवा नेतृत्व का नया चेहरा देने का प्रयास किया है। हालांकि भाजपा के सामने चुनौती केवल संगठन विस्तार की नहीं है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, रोजगार के अवसर, स्टार्टअप, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर युवाओं की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यदि युवा मोर्चा इन विषयों पर प्रभावी संवाद स्थापित कर पाता है, तो भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर यदि युवा वर्ग के मुद्दों का प्रभावी समाधान नहीं हुआ, तो विपक्ष इन्हीं प्रश्नों को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार, रोहित मिश्रा की नियुक्ति भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें जातीय संतुलन के साथ-साथ 'युवा नेतृत्व' को भी 2027 की चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आवाज उठाई

प्रदीप तिवारी 'आसरा'

अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और कार्रवाई की जरूरत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आवाज उठाई है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और कार्रवाई की जरूरत है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने उत्तर प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की गड़बड़ी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस धांधली को रोकने के लिए सरकार को क्यूआर कोड आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए, ताकि प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता तुरंत चेक की जा सके। यह मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे देश में फर्जी एससी-एसटी जाति प्रमाण-पत्रों की आड़ में हजारों-लाखों लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जो असली शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों की हकमारी कर रहा है। कई लोग इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं और कुछ तो विधायक व सांसद तक बन गए हैं।

जब इन मामलों में शिकायत होती है या कोर्ट में केस दायर किया जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल हो जाती है कि तब तक आरोपी का कार्यकाल पूरा हो जाता है। नतीजा? असली एससी-एसटी समुदाय के युवा, जिन्हें संविधान के माध्यम से यह सुरक्षा दी गई थी, वह पीछे छूट जाते हैं। यह धांधली सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ है।

आरक्षण का पूरा उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना था, न कि कुछ चालाक और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाना। अगर फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों, बनवाने वालों और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तो आने वाले समय में इस व्यवस्था पर लोगों का विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा।कोर्ट ने जो सुझाव दिया है, उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए

पूरे देश में जाति प्रमाण-पत्रों का डिजिटल डेटाबेस बनाया जाए। हर प्रमाण-पत्र पर क्यूआर कोड अनिवार्य हो, जिससे रीयल-टाइम वेरिफिकेशन हो सके। फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाने और इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा का प्रावधान (जेल+जुर्माना+पद से बर्खास्तगी)।

पुराने संदिग्ध प्रमाण-पत्रों की बड़े स्तर पर जांच और रिव्यू

सरकार, खासकर केंद्र सरकार को इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। एससी-एसटी समुदाय के वास्तविक हितों की रक्षा करना हर संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है। अगर अब भी हम इस गंभीर फजीर्वाड़े पर लगाम नहीं लगाएंगे, तो संविधान निमार्ताओं का सपना,असली सामाजिक न्याय, अधूरा ही रह जाएगा। सच का साथ दें। असली वंचितों के अधिकार बचाएं।

प्रयागराज के बहाने पूर्वांचल साधने की कोशिश

भाजपा के नए संगठन में बढ़ती हिस्सेदारी के राजनीतिक मायने

शिवा शंकर पाण्डेय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक फेरबदल कभी केवल पदों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि वह आगामी चुनावी रणनीति का संकेत भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश संगठन में प्रयागराज (इलाहाबाद) को जिस प्रकार प्रमुख स्थान दिया गया है, उसने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रयागराज को मिला प्रतिनिधित्व यह संकेत देता है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज के माध्यम से पूरे पूर्वांचल को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रयागराज केवल एक जिला नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति, शिक्षा, न्यायपालिका, धार्मिक चेतना व ब्राह्मण समाज का प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। इसलिए भाजपा का यह संगठनात्मक संदेश केवल स्थानीय संतुलन नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक गणित का हिस्सा माना जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है प्रयागराज?

प्रयागराज का प्रभाव केवल अपनी संसदीय और विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। इसका सामाजिक और राजनीतिक असर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिजार्पुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, चित्रकूट, फतेहपुर और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों तक तगड़ा दिखाई देता है। शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका से जुड़े हजारों परिवारों का सामाजिक प्रभाव पूरे पूर्वांचल में फैला हुआ है।

भाजपा ने लंबे समय से प्रयागराज को वैचारिक और संगठनात्मक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। कुंभ, महाकुंभ, संगम क्षेत्र का विकास, कॉरिडोर परियोजनाएं तथा धार्मिक पर्यटन के विस्तार ने इस शहर को पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति का भी महत्वपूर्ण आधार बनाया है। नए संगठन में प्रयागराज की मजबूत मौजूदगी, प्रदेश संगठन में प्रयागराज से तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाना, सामान्य राजनीतिक

नियुक्ति नहीं मानी जा सकती। इसके साथ एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से आने वाले रोहित मिश्रा को भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी विशेष महत्व रखता है।

इन नियुक्तियों से भाजपा ने कई स्तरों पर संदेश देने का प्रयास किया है—

प्रयागराज भाजपा की राजनीतिक प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है।
पूर्वांचल के प्रभावशाली जिलों को संगठनात्मक नेतृत्व से जोड़ने की कोशिश।
ब्राह्मण समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व।
युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति।
जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का समन्वय।

ब्राह्मण राजनीति का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष लगातार यह प्रचार करता रहा कि भाजपा में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है। ऐसे समय में प्रयागराज के ब्राह्मण चेहरे रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना संगठनात्मक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा यह बताना चाहती है कि संगठन में युवाओं और ब्राह्मण समाज दोनों को पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। यह नियुक्ति उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का संदेश है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं।

पूर्वांचल की चुनावी चुनौती

2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को यह संकेत दिया कि पूर्वांचल में पहले जैसी एकतरफा स्थिति अब नहीं रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कई क्षेत्रों में भाजपा को कड़ी चुनौती दी। ऐसे में भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर उन जिलों को मजबूत करना शुरू किया है जिनका व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव है। प्रयागराज उसी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यदि प्रयागराज का संगठन मजबूत होता है तो उसका असर आसपास के अनेक जनपदों पर भी पड़ सकता है। भाजपा इसी राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाना चाहती है।

महाकुंभ के बाद नई राजनीतिक जमीन

महाकुंभ के सफल आयोजन ने प्रयागराज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने भाजपा को यह विश्वास भी दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे अभी भी उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हैं। अब संगठन में प्रयागराज को बढ़ी हुई हिस्सेदारी देकर भाजपा इस सांस्कृतिक पूंजी को राजनीतिक संगठन में बदलने का प्रयास करती दिखाई देती है।

जातीय संतुलन की राजनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी दल जातीय समीकरणों की अनदेखी नहीं कर सकता। भाजपा ने अपने नए संगठन में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी सभी सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलना चाहती है। प्रयागराज के प्रतिनिधित्व में भी यही संतुलन दिखाई देता है। यहां ब्राह्मण नेतृत्व के साथ अन्य सामाजिक वर्गों को भी स्थान देकर भाजपा ने सामाजिक समावेशन का संदेश देने का प्रयास किया है।

विपक्ष के लिए चुनौती

सपा का पारंपरिक प्रभाव यादव और मुस्लिम मतदाताओं में मजबूत माना जाता है, जबकि कांग्रेस प्रयागराज की ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा का मजबूत संगठन विपक्ष की रणनीति को कठिन बना सकता है। यदि संगठन बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से सक्रिय हो गया तो विपक्ष को केवल मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा।

क्या केवल संगठन पर्याप्त होगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन चुनाव जिताने का आधार तो बन सकता है, लेकिन अंतिम सफलता जनता के बीच किए गए कार्यों, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर भी निर्भर करेगी। यदि संगठन जनता से लगातार संवाद बनाए रखता है और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाता है, तभी यह प्रतिनिधित्व चुनावी लाभ में परिवर्तित हो सकेगा।

प्रयागराज से पूरे पूर्वांचल तक संदेश

भाजपा का यह संगठनात्मक प्रयोग केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है। इसका संदेश पूरे पूर्वांचल के कार्यकताओं के लिए है कि क्षेत्र को पार्टी की भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान मिलने वाला है। यह रणनीति पूर्वांचल में नए नेतृत्व को तैयार करने, बूथ संगठन को मजबूत करने तथा सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

2027 की तैयारी अभी से

राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी मतदान से कई वर्ष पहले शुरू कर देते हैं। भाजपा ने भी संगठनात्मक नियुक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि उसका पूरा ध्यान अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। प्रयागराज को मजबूत संगठनात्मक प्रतिनिधित्व देकर भाजपा एक ऐसे राजनीतिक केंद्र का निर्माण करना चाहती है जहां से पूरे पूर्वांचल में चुनावी संदेश, संगठनात्मक ऊर्जा और नेतृत्व का विस्तार किया जा सके। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए संगठन में प्रयागराज को मिली असाधारण हिस्सेदारी केवल संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भाजपा पूर्वांचल में अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है।

केवल संगठनात्मक प्रतिनिधित्व चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होता। जनता के मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता व सामाजिक विश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर भी इतना स्पष्ट है कि भाजपा ने प्रयागराज को केवल एक जिला नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीतिक धुरी मानते हुए अपनी रणनीति तैयार की है।

आगामी महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रयागराज के माध्यम से तैयार किया गया यह संगठनात्मक मॉडल वास्तव में पूरे पूर्वांचल में भाजपा की राजनीतिक बढ़त को मजबूत कर पाता है, या विपक्ष अपने नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के सहारे इस चुनौती का प्रभावी जवाब देने में सफल होता है। प्रश्न 2027 की उप्र की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।

(लेखक विचार सेतु में समन्वय संपादक)

पीओके आंदोलनकारियों का भारत से समर्थन मांगना पाक के मुंह पर तमाचा

संजय मग्गू

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले कई हफ्तों से नागरिक अधिकारों को लेकर चल रहा आंदोलन गहराता जा रहा है। पांच जुलाई को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने चक्काजाम का आह्वान किया, तो पाकिस्तान सरकार ने ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इससे मुजफ्फराबाद शासन के खिलाफ बगावत की आंच और तेज हो उठी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने वीडियो संदेश जारी कर भारत के लोगों से समर्थन माँगा है। खान ने भारत में जम्मू, कश्मीर, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, लद्दाख, कारगिल और कुछ अन्य जगहों के लोगों से समर्थन की अपील की है। कुछ वीडियो और रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत की ओर रुख दिखाने और भारत के साथ जुड़ने जैसी भावनाएं भी व्यक्त की गई हैं। वैसे तो पीओके पिछले कई वर्षों से सुलग रहा है। लोगों में सुलग रहे असंतोष ने अब ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने पीओके में मुजफ्फराबाद प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वैसे तो ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पिछले तीन साल से पीओके में आंदोलन छेड़ रखा है। जेएएसी के आंदोलन की शुरूआत सन 2023 में गेहूं और बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की। पीओके में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और महंगाई के

साथ-साथ बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। जेएएके ने इन्हीं मुद्दों को लेकर धीरे-धीरे पाक अधिकृत कश्मीर की जनता में अपनी पैठ बनानी शुरू की और आज वह पीओके की जनता की प्रमुख आवाज बन चुकी है। इन दिनों पीओके में जो आंदोलन चल रहा है, वह पीओके विधानसभा में विस्थापितों के नाम पर बारह सीटों पर होने वाली चुनावी प्रक्रिया को समाप्त करने को लेकर है।

पीओके की तथाकथित विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 33 सीटों पर पाकिस्तान निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। इन सीटों पर चुने गए प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। 12 सीटें उन विस्थापितों के लिए छोड़ी गई हैं जो सन 1947 और 1962 में जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बस गए हैं। बाकी बची आठ सीटों पर प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं। इन आठ में पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, एक सीट पर उलेमा, एक पर विस्थापित कश्मीरी और एक पर तकनीशियन को मनोनीत किया जाता है। भारत में भी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के समय 24 सीटें पीओके के लिए छोड़ी जाती हैं जिन पर कभी चुनाव नहीं होता है। पाक अधिकृत कश्मीर की विधानसभा में विस्थापितों के लिए आरक्षित बारह सीटों और मनोनयन वाली आठ सीटों को लेकर ही पाकिस्तानी सरकार और सेना अपना सारा खेल करती है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पिछले कुछ महीनों से विस्थापितों के लिए आरक्षित बारह सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। मानवाधिकार आयोग और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि रावलकोट, मुजफ्फराबाद और कोटली सहित अन्य इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 30 से 53 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक्शन कमेटी के सदस्य और पीओके के आम नागरिक शामिल हैं। 1100 से अधिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के कार्यकताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है।

पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है, यह पूरी दुनिया को मालूम है। विदेशी कर्जों के बोझ से दबे पाकिस्तान में गरीबी और महंगाई अपने चरम पर है। उद्योग और व्यापार चौपट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी जनता को पाई-पाई के लिए मोहताज और एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होना पड़ता है। उस पर पीओके की जनता के साथ किया जाने वाला दोयम दर्जे का व्यवहार उनके असंतोष को और बढ़ावा दे रहा है। अगस्त 2023 में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन छेड़ा। मांग जनहित में थी, तो पीओके जनता भी इनके साथ उठ खड़ी हुई। मई 2024 में मंगला बांध से पनबिजली उत्पादन की कीमत पर रियायती आटा उपलब्ध कराने और बिजली के टैरिफ की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस बलों के उकसावे पर जल्दी ही यह आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस और पाक रेंजर्स को मानो दमन का अधिकार मिल गया। लेकिन जल्दी पाक सरकार को जेएएसीकी मांग को मानना पड़ा। लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ा ही था कि कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर अध्यादेश पारित किया, तो मानो एक बार फिर असंतोष का ठंडा पड़ा ज्वालामुखी फूट पड़ा। लोगों ने सरकार की इस कार्रवाई को बुनियादी नागरिक और आर्थिक अधिकर को छीनने का प्रयास माना।

एक बार फिर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी मैदान में कूद पड़ी। उसने 38 मांगों को लेकर सितंबर 2025 में आंदोलन शुरू कर दिया। हमेशा की तरह पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से दमन चक्र तेज हुआ, तो आंदोलन हिंसक हो गया। कुछ लोग मारे गए, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन विस्थापितों के नाम पर बारह सीटों पर होने वाले चुनाव का मुद्दा अभी तक अटका हुआ है। सच तो यह है कि पाकिस्तान के अधिकतर प्रांत संघर्ष की आग में जल रहे हैं। बलूचिस्तान में पिछले कई दशकों से विद्रोह की आग धधक रही है। पाकिस्तान सरकार द्वारा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कोयले की लूट के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी काफी दिनों से संघर्ष कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा में उसे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सिंध और दक्षिण पंजाब में भी भारी असंतोष है। अफगानिस्तान से उसके रिश्ते काफी जटिल होते जा रहे हैं। सीमा विवाद और अफगानी घुसपैठियों का मामला दोनों को हिंसक कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहा है। पाक-अफगान सीमा पर आए दिन होने वाली गोलीबारी से हालत बदतर होते जा रहे हैं। भारत सन 1947 से लेकर आज तक भारत-पाकिस्तान के संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं पाए हैं। पाकिस्तान सरकार कभी अपनी धूर्तता और कुटिलता से बाज आई ही नहीं। ऐसी स्थिति में संबंधों के सामान्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पीओके की जनता के साथ किए जाने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार और मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता ही रहा है। दुनिया भर की निगाहें अब पीओके पर ठहरने लगी हैं। इससे पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर थू-थू होने लगी है। दुनिया को पाक का दोहरा चरित्र समझ में आने लगा है।

(लेखक देश रोजाना के प्रधान संपादक हैं।

नीट पेपर लीक।

सपनों पर सवाल, भरोसे का संकट

दीपक तिवारी

मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का एकमात्र राष्ट्रीय माध्यम मानी जाने वाली नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण अब शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी संस्थागत चुनौती बन चुका है। परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई हैं। इस घटना ने परीक्षा संचालन की सुरक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और लाखों विद्यार्थियों के समान अवसर के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार को कानून सख्त करने से लेकर जांच व्यवस्था मजबूत करने तक कई कदम उठाने पड़े।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी का पेपर लीक प्रकरण केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के भरोसे पर गहरी चोट बनकर सामने आया है। हर वर्ष 20 लाख से अधिक छात्र एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा देते हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका भी उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय मानी जाती है, जिन्होंने केवल अपनी मेहनत के भरोसे परीक्षा दी। यही कारण है कि इस प्रकरण ने प्रतिभा आधारित चयन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। जांच में सामने आए तथ्यों से संकेत मिले कि प्रश्नपत्र लीक कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि कथित रूप से दलालों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य सहयोगियों के माध्यम से संचालित संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। इसी पृष्ठभूमि में जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई और कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की पड़ताल की गई। इस पूरे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' लागू किया, जिसके तहत पेपर लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर कठोर दंड और भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून के साथ-

साथ उसका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन ही परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल कर सकता है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल पारंपरिक सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं। एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्नपत्र, सुरक्षित सर्वर आधारित वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल ऑडिट ट्रेल जैसी तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाना आवश्यक हो गया है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और गोपनीयता मजबूत रहे।

पेपर लीक की घटनाओं का सबसे गहरा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वर्षों की तैयारी के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को यह महसूस हो कि अवैध तरीके से भी सफलता हासिल की जा सकती है, तो व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विशेषज्ञ निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम परीक्षा प्रणाली को देश के भविष्य के लिए अनिवार्य मान रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और देश की प्रतिभा का मूल्यांकन भी है। यदि भारत को वैश्विक स्तर पर सक्षम चिकित्सा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करना है, तो परीक्षा प्रणाली को भी उतना ही सुरक्षित, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना होगा। यही करोड़ों छात्रों के सपनों और राष्ट्र के भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होगी।

भारत में एमबीबीएस सीटों की तस्वीर (2026)

कुल मेडिकल कॉलेजः 823

कुल एमबीबीएस सीटेंः 1,29,602

सरकारी मेडिकल कॉलेजः लगभग 430

सरकारी कॉलेजों में सीटेंः लगभग 61,000

निजी/ट्रस्ट/डीम्ड मेडिकल कॉलेजः लगभग 393

निजी, ट्रस्ट व डीम्ड कॉलेजों में सीटेंः लगभग 68,600

नीट - यूजी परीक्षा के दिलचस्प तथ्य

हर वर्ष 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी नीट-यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं।

यानी औसतन हर 15-16 अभ्यर्थियों पर केवल एक एमबीबीएस सीट उपलब्ध होती है।

बीते दशक में मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या दोगुने से अधिक बढ़ी है।

सरकारी सीटों की तुलना में निजी क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत तेज रहा है।

सबसे बड़ी आबादी वाले देश में डॉक्टरों की कमी

नीट-यूजी की बात हो रही है तो देश में चिकित्सा व्यवस्था पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। भारत में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा अब केवल संख्या तक सीमित नहीं रह गया है, डॉक्टरों का असमान वितरण सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 13.88 लाख पंजीकृत एलोपैथिक व 7.51 लाख आयुष चिकित्सक हैं। इनमें से 80% की उपलब्धता मानने पर डॉ.-जनसंख्या अनुपात 1:811 बैठता है, जिसे सरकार वैश्विक मानकों के अनुरूप मानती है।

फिर चिकित्सकों की कमी क्यों महसूस होती है?

अधिकांश विशेषज्ञ डॉक्टर बड़े शहरों में केंद्रित हैं। ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) व व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में हजारों पद रिक्त हैं। कई सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों व फैकल्टी की कमी के कारण मरीजों का भार बढ़ जाता है। देशभर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं व एमबीबीएस व पीजी सीटों में लगातार वृद्धि की जा रही है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने की योजना लागू है।

टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसी डिजिटल व्यवस्था

जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम (ज़िला निवास कार्यक्रम) के तहत पीजी छात्रों को जिला अस्पतालों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और विशेष भत्ते दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ परामर्श की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में यूपी सरकार ने एक केंद्रीयकृत प्रणाली बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। ताकि आकस्मिक स्थिति में किसी को यहां-वहां भटकने की नौबत न आए।

क्या पुतिन ने एक वाक्य में बदलती दुनिया का सच कह दिया?

रिश्तों की असली मुद्रा भरोसा होती है, रूस ने वही निवेश किया

रूस की आंखों में भारत: भरोसा, संतुलन और आने वाला भविष्य

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

इतिहास के कठिन दौर ही रिश्तों की असली परीक्षा लेते हैं। ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत को 'दुनिया के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक' बताना महज कूटनीतिक वाक्य नहीं है। 4 जून 2026 को सेंट पीटर्सबर्ग में दिया गया उनका बयान ऐसे समय आया, जब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया नए राजनीतिक खांचों में बंटती दिख रही है। प्रतिबंधों से घिरा रूस अपने विश्वसनीय मित्रों को पहचान रहा है और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अलग सम्मान पा रहा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत पर पश्चिमी दबाव को 'निष्फल और प्रतिकूल' बताया। यह केवल मित्रता की प्रशंसा नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व की स्वीकारोक्ति है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शब्द अक्सर परिस्थितियों का आईना होते हैं। पुतिन की भारत-प्रशंसा को भी इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पश्चिमी प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव का सामना कर

रहा है। ऐसे समय में भारत उन विरले देशों में रहा, जिसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार रूस से संबंध बनाए रखे। न उसने किसी दबाव के आगे झुकना स्वीकार किया, न अपनी विदेश नीति का मार्ग बदला। पुतिन भलीभांति समझते हैं कि भारत जैसा मित्र केवल आर्थिक सहयोगी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संबल भी है। इसलिए उनका यह बयान प्रशंसा से अधिक उस विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिस पर रूस भविष्य की अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार देखता है।

पुतिन के बयान का एक संभावित संकेत चीन की ओर भी है। रूस और चीन भले ही अटूट साझेदारी का दावा करें, लेकिन उनके संबंधों में रणनीतिक सतर्कता बनी रहती है। चीन की बढ़ती आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति ने एशिया का शक्ति-संतुलन बदल दिया है। मॉस्को समझता है कि बीजिंग पर अत्यधिक निर्भरता उसकी स्वतंत्र भूमिका को सीमित कर सकती है। ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंध उसे संतुलन देते हैं। यही कारण है कि पुतिन ने ब्रह्मोस, रक्षा सहयोग और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी साझेदारी का विशेष उल्लेख किया। इसे मुख्य रूप से चीन के विरुद्ध संदेश न मानकर, एशिया में शक्ति-संतुलन साधने की रूस की दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वतंत्रता है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर पड़ रहे अमेरिकी दबाव के बीच उसकी नीति की सराहना की। अमेरिका लंबे समय से रूस से जुड़े ऊर्जा व रक्षा संबंधों को लेकर भारत को अपने अधिक निकट लाने का प्रयास करता रहा है। इसके बावजूद नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि उसके निर्णय राष्ट्रीय हितों से संचालित होंगे, किसी बाहरी दबाव से नहीं। पुतिन ने इसी आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत जैसे उभरते राष्ट्र पर दबाव डालना उलटा पड़ सकता है। उनका संदेश केवल वाशिंगटन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अब अपनी राह स्वयं तय करने वाली शक्ति है।

भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्ति उसका संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है। भारत एक ओर रूस से ऊर्जा, रक्षा उपकरण और सामरिक सहयोग प्राप्त कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और सुरक्षा साझेदारी भी मजबूत कर रहा है। चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यापारिक संबंध भी बने हुए हैं। संतुलन भारत को वैश्विक राजनीति में अलग पहचान देता है। पुतिन ने मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों और तेज विकास दर की सराहना करते हुए संकेत दिया कि भारत किसी शक्ति-गुट का अनुसरण करने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का एक स्वतंत्र व प्रभावशाली शक्ति केंद्र बन चुका है।

भारत-रूस संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी नई मजबूती हासिल कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार लगभग 68.7अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें रूसी तेल, गैस व कोयले की प्रमुख भूमिका रही। पुतिन द्वारा 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य का उल्लेख इस बात का संकेत है कि रूस भारत को केवल मित्र नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार मानता है। ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, रक्षा उत्पादन व उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देश एक-दूसरे की क्षमताओं को अपने विकास का महत्वपूर्ण आधार मान रहे हैं।

मित्रता जितनी गहरी होती है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक होती हैं। भारत-रूस संबंधों के सामने भी व्यापार असंतुलन, भुगतान व्यवस्था की बाधाएं, रक्षा खरीद में भारत की नई प्राथमिकताएं और रूस-चीन की बढ़ती निकटता जैसे प्रश्न मौजूद हैं। इसलिए पुतिन ने भारत-चीन सीमा पर तनाव कम करने के प्रयासों का स्वागत किया। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि रूस का यह संदेश था कि वह एशिया में स्थिरता और संतुलन का पक्षधर है। साथ ही, वह यह भरोसा भी दिलाना चाहता है कि चीन से उसके संबंध भारत के हितों की कीमत पर नहीं हैं। भारत के लिए यह आश्वासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश नीति का आधार केवल राष्ट्रीय हित हैं।

विश्व राजनीति में कुछ वक्तव्य तत्कालीन घटनाओं से आगे जाकर भविष्य की दिशा भी बताते हैं। पुतिन का भारत को 'भरोसेमंद साझेदार' कहना ऐसा ही संकेत है। यह केवल भारत-रूस संबंधों की निकटता नहीं, बल्कि आकार ले रही नई वैश्विक व्यवस्था की झलक है। एकध्रुवीय प्रभुत्व का दौर पीछे छूट रहा है नई शक्तियां उभर रही हैं। ब्रिक्स का विस्तार, वैश्विक दक्षिण का बढ़ता प्रभाव और भारत की भूमिका इसी परिवर्तन के संकेत हैं। रूस का यह सार्वजनिक विश्वास एक स्पष्ट संदेश देता है, भारत अब किसी समीकरण का हिस्सा नहीं, स्वयं एक निर्णायक समीकरण है। इसलिए पुतिन का यह बयान केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बदलती विश्व व्यवस्था की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

Will AI Drink India Dry?

By Rajeev Narayan

Journalist

One day soon, every Indian may wake up to an extraordinary irony. The same nation whose residents queue up each day before tankers and whose village women walk to distant wells in blistering summer heat to find pots of water could find itself supplying millions of litres of the elixir to cool artificial intelligence servers owned by global technology giants. As the world embraces the 'AI Age', an itchy truth is fast emerging. The future of AI will depend less on algorithms and more on access to water, electricity and land.

AI is sold as clean, invisible, futuristic and floating in 'the Cloud', detached from realities of geography and natural resources. But the truth is more industrial. AI runs on gigantic data centres packed with rows of high-tech servers that gulp up staggering quantities of cooling water and enormous amounts of electricity every minute. They require elaborate cooling systems, non-stop power supply, massive land acquisition and Machiavellian infrastructure.

Many communities in the United States took to the streets recently to fight data centre expansion. In the drought-prone areas of Arizona and Texas, citizens marched against groundwater depletion, spiking power demand and ecological stress linked to hyperscale data centres. Studies now question whether the average citizen should bear these daily costs just to enable global tech companies to train ever-larger AI models.

India Faces the Stress

Despite this sobering truth, India's ambition to emerge as a global AI and data-centre hub is projected as a 'strategic triumph'. Investments worth billions are being made and Indian states are huffing and puffing to win the race. Cries of 'Digital Leadership', 'AI Sovereignty' and 'Future-Ready infrastructure' dominate policy discussions and presentations. But beneath the optimism lies a tough question: can a water-stressed and energy-poor nation realistically absorb the burden of being the world's AI engine room?

The question pops up because India's environmental arithmetic is already strained. It hosts 18 per cent of the global population, but has only 4 per cent of the world's freshwater resources. Groundwater depletion has become a headache and urban cities routinely face water shortages. Rivers remain polluted. Heatwaves are growing longer and harsher, with climate change baring its fangs.

Into this fragile equation enters the AI data centre. In January, the Economic Survey described AI infrastructure as a 'double-edged sword', noting that large data centres consume enormous amounts of water and electricity. This is no operational detail. Cooling is central to the survival of AI systems. Advanced processors generate massive heat as they operate non-stop, making cooling a life-saving intervention. Water is the cheapest, most efficient way to cool things off.Studies show that a single AI-linked data centre can consume millions of litres of water daily. Researchers worry about the expanding water footprint associated with AI model training and server cooling systems. The IEA has cautioned that power demand from AI and data centres could surge sharply. Very soon.

India's AI Headache

In India, the situation is grave because data-centre clusters are emerging in regions already facing water pressure. Bengaluru has been living with killing water shortages in recent years, forcing people to rely on private tankers. Chennai has battled

fears of 'Day Zero' situations for long. Hyderabad, Pune and parts of Delhi-NCR are experiencing near-death groundwater stress.

The concern is neither theoretical nor theatrical. If normal demand is already taxing local systems, what will happen when hyper AI facilities begin competing for the same water? The danger lies in concentration. Demand calculations may appear manageable on paper, but the ecological impact is shocking. People living around new data centres may soon face declining groundwater tables and rising utility pressures.

Another challenge is electricity. AI is as addictive as it is power-hungry. High-octane computing clusters operate round-the-clock, necessitating stable grids. Worldwide, analysts describe power availability as one of the biggest constraints on future AI expansion. Admittedly, India has made progress in expanding power generation and green-energy. Solar deployment has grown. Transmission infrastructure has widened. Yet, India faces power pressures during peak summer months, with heatwaves and rising air-conditioning demand. Nearly all regions see outages, shutdowns and distribution failures. Upcoming AI and data centre infrastructure will only intensify these pressures.

India's Green Paradox

The irony is waiting to bite us in the behind. AI is pushed as a tool to optimise systems, improve efficiencies and fight climate change. Yet, the infrastructure powering AI will itself raise emissions if not supported through clean-energy sources. India, thus, faces a difficult balancing act. It cannot isolate itself from the global AI race. And it should not. For AI will shape future competitiveness across all industry sectors. India requires strong domestic computing capabilities to remain technologically relevant in the coming decades.

But strategic participation should not translate into ecological surrender. The silent costs of technological progress have to be met head on. Data-centre growth requires land, substations, transmission corridors, roads and construction ecosystems. This creates green disruption and urbanisation pressure. Questions

around e-waste disposal, thermal pollution and ecological carrying capacity remain insufficiently discussed.

Then comes the issue of employment. Unlike manufacturing, which generates labour-intensive supply chains, data centres are automated once operational.

After the setup is complete, employment generation is limited. Thus, the environmental burden far outweighs the job creation benefits. This creates a dilemma. As millions struggle for reliable water, power and infrastructure, should scarce resources serve global server farms rather than local developmental priorities?

The question may be provocative, but it is becoming impossible to ignore. Public resistance in parts of the US reflects the same anxiety. People are beginning to realize that the digital economy is not immaterial. The cloud is not floating somewhere in the sky. It sits on land, consumes water and burns electricity.

Global Tinkering

The world is tinkering with alternatives to reduce these green costs. Some are investing in advanced cooling tech to cut freshwater dependence. Others are exploring immersion cooling, closed-loop systems. Nordic nations are using colder climates to cut cooling needs. China is experimenting with underwater data centres that use ocean temperatures for natural cooling. These highlight a simple reality – that the future of AI will depend not only on computing power, but also on ecological sustainability. India has an opportunity to shape this transition smartly. Rather than celebrate every incoming data-centre investment, it needs to post stricter norms and carrying-capacity assessments. Water accounting systems, renewable-energy obligations, wastewater recycling needs and region-specific green clearances are needed. Geographic planning is important too, for water-stressed regions should not become AI's cheer boys and girls simply because the incentives are attractive.

Tough Balancing Act

India does not need to reject AI. That would be neither practical nor strategic. But it must refuse to become an ecological shock absorber of the global digital economy. The question is not whether India can host the world's AI infrastructure. It is whether India can do this without forcing its citizens into a battle over water, electricity and environmental survival. A nation where millions struggle for reliable drinking water cannot afford to treat ecological costs as secondary details in the race for technological prestige.

Yes, AI will reshape the future. But if nations begin sacrificing rivers, groundwater and energy security to power endless server farms, the world will discover a deadly paradox: that humanity built intelligent machines but behaved unwisely with its own life-sustaining natural resources. That is the conversation India must begin today- before the hum of servers grows louder than the sound of the warning bells.

1857 की क्रांति का प्रथम शहीद : मंगल पाण्डे

(मंगल पाण्डे की जयंती पर विशेष)

राम शिव मूर्ति यादव

1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखती है। यह क्रांति तात्कालिक रूप से विफल भले ही रही हो, पर इसने ही आजादी के लिए चलने वाली लंबी और सुनियोजित लड़ाई की संगठित नींव रखी। इस क्रांति में तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी, उन्हीं में से एक मंगल पांडे भी थे, जिन्हें 1857 की क्रान्ति का प्रथम शहीद माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को जन्मे मंगल पाण्डे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इंफेन्ट्री के सिपाही थे। मात्र 22 साल की उम्र में सन1849 में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए।

कहा जाता है कि पूरे देश में एक ही दिन 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ करने का निश्चय किया गया था, पर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पाण्डे (19 जुलाई 1827-8 अप्रैल 1857) की विद्रोह से उठी ज्वाला वक्त का इन्तजार नहीं कर सकी और प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आगाज हो गया। मंगल पाण्डे को 1857 की क्रान्ति का पहला शहीद सिपाही माना जाता है। इस विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को दी गई इस नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिये कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारुद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनायी जाती है।

29 मार्च 1857, दिन रविवार-उस दिन जनरल जान हियर्से अपने बंगले में आरम्भ कर रहा था कि एक लेफ्टिनेंट बद्हवास सा दौड़ता हुआ आया और बोला कि देसी लाइन में दंगा हो गया। खून से रंगे अपने घायल लेफ्टिनेंट की हालत देखकर जनरल जान हियर्से अपने दोनों बेटों को लेकर 34वीं देसी पैदल सेना की रेजीमेन्ट के परेड ग्राउण्ड की ओर दौड़ा। उधर धोती-जैकेट पहने 34वीं देसी पैदल सेना का जवान मंगल पाण्डे नंगे 5 ही एक भरी बन्दूक लेकर क्वाटर गार्ड के सामने बड़े ताव मे चहलकदमी कर रहा था और रह-रह कर अपने साथियों को ललकार रहा था-

सिपाहियों को दी गई इस नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिये कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारुद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था।

'अरे! अब कब निकलोगे? तुम लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। आओ, सब मेरे पीछे आओ। हम इन्हें अभी खत्म कर देते हैं।' लेकिन अफसोस किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पर मंगल पाण्डे ने हार नहीं मानी और अकेले ही अंग्रेजी हुकूमत को ललकारता रहा। तभी अंग्रेज सार्जेंट मेजर जेम्स थार्नटन ह्यसन ने मंगल पाण्डे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह सुन मंगल पाण्डे का खून खौल उठा और उसकी बन्दूक गरज उठी। सार्जेंट मेजर ह्यसन वहीं लुढ़क गया। अपने साथी की यह स्थिति देख घोडे. पर सवार लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बेम्पडे हेनरी वॉग मंगल पांडे की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वह उसे काबू कर पाता, मंगल पाण्डे ने उस पर गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली घोड़े को लगी और वॉग नीचे गिरते हुये फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अब दोनों आमने-सामने थे। इस बीच मंगल पाण्डे ने अपनी तलवार निकाल ली और पलक झपकते ही वॉग के सीने और कन्धे को चीरते हुये निकल गई। तब तक जनरल जान हियर्से घोड़े पर सवार परेड ग्राउंड में पहुंचा और यह दृश्य देखकर भौंचक्का रह गया।

जनरल हियर्से ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को हुक्म दिया कि मंगल पाण्डे को तुरन्त गिरफ्तार कर लो पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तब जनरल हियर्से ने शेख पल्टू को मंगल पाण्डे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। शेख पल्टू ने मंगल पाण्डे को पीछे से पकड़ लिया। स्थिति भयावह हो चली थी। मंगल पाण्डे ने गिरफ्तार होने से बेहतर मौत को गले लगाना उचित समझा और बन्दूक की नाली अपने सीने पर रख पैर के अंगूठे से फायर कर दिया। लेकिन होनी को कुछ और

14 मई 1857 को गर्वनर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंगस ने मंगल पांडे का फांसीनामा अपने आधिपत्य में ले लिया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, बंगाल में मंगल पांडे को प्राण दण्ड दिये जाने के ठीक सवा महीने बाद, जहां से उसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानान्तरित कर दिया गया था। सन 1905 के बाद जब लार्ड कर्जन ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश की थल सेनाओं का मुख्यालय बनाया गया तो मंगल पांडे का फांसीनामा जबलपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। जबलपुर के सेना आयुध कोर के संग्राहलय में मंगल पाण्डे का फांसीनामा आज भी सुरक्षित रखा है। इसका हिन्दी अनुवाद निम्नवत है-

-जनरल आर्डर्स, बाय हिज एक्सीलेंसी
द कमांडर इन चीफ, हेड क्वार्टर्स, शिमला

18 अप्रैल 1857: गत 18 मार्च 1857, बुधवार को फोर्ट विलियम्स में सम्पन्न कोर्ट मार्शल के बाद कोर्ट मार्शल समिति 6 अप्रैल 1857, सोमवार के दिन बैरकपुर में पुनः इकट्ठा हुई तथा 5वी कंपनी की 34वीं रेजीमेंट नेटिव इनफेंट्री के 1446 नं. के सिपाही मंगल पाण्डे के खिलाफ लगाये गये निम्न आरोपों पर विचार किया।

आरोप (1) बगावतः- 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में परेड मैदान पर अपनी रेजीमेंट की क्वार्टर गार्ड के समक्ष तलवार और राइफल से लैस होकर अपने साथियों को ऐसे शब्दों में ललकारा, जिससे वे उत्तेजित होकर उसका साथ दें तथा कानूनों का उल्लंघन करें।

आरोप (2) इसी अवसर पर पहला वार किया गया तथा हिंसा का सहारा लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सार्जेन्ट-मेजर जेम्स थार्नटन ह्यूसन और लेफ्टिनेंट-एडजुटेंट बेंपडे हेनरी वॉग जो 34वीं रेजेमेंट नेटिव इनफेंट्री के ही थे, पर अपनी राइफल से कई गोलियां दागीं तथा बाद में उल्लिखित लेफ्टिलेन्ट वॉग और सार्जेट मेजर ह्यूसन पर तलवार के कई वार किये।

निष्कर्षः- अदालत 5वी कंपनी की 34वीं रेजीमेन्ट नेटिव इनफेंट्री के सिपाही नं. 1446, मंगल पाण्डे को उक्त आरोपों का दोषी पाती है।

सजाः- अदालत 5वी कंपनी की 34वीं रेजीमेंट नेटिव इनफेंट्री के सिपाही नं. 1446, मंगल पाण्डे को मृत्युपर्यन्त फांसी पर लटकाए रखने की सजा सुनाती है।

अनुमोदित एवं पुष्टिकृत
(हस्ताक्षरित) जे.बी.हरसे, मेजर जनरल कमाण्डिंग,
प्रेसीडेंसी डिवीजन
बैरकपुर, 7 अप्रैल 1857

टिप्पणीः- 5वी कंपनी की 34वीं रेजीमेंट नेटिव इनफेंट्री के सिपाही नं.1446, मंगल पाण्डे को कल 8 अप्रैल को प्रातः साढ़े 5 बजे ब्रिगेड परेड पर समूची फौजी टुकड़ी के समक्ष फांसी पर लटकाया जायेगा।

(हस्ताक्षरित) जे.बी.हरसे, मेजर जनरल, कमांडिंग प्रेसीडेंसी डिवीजन

इस आदेश को प्रत्येक फौजी टुकड़ी की परेड के दौरान और खास तौर से बंगाल आर्मी के हर हिन्दुस्तानी सिपाही को पढ़कर सुनाया जाये।

बाय ऑर्डर ऑफ हिज एक्सीलेंसी
द कमांडर-इन-चीफ
सी.चेस्टर, कर्नल।

ही मंजूर था, सो मंगल पाण्डे सिर्फ घायल होकर ही रह गए। तुरन्त अंग्रेजी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर बन्दी बना लिया और मंगल पाण्डे के कोर्ट मार्शल का आदेश हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने 6 अप्रैल को फैसला सुनाया कि मंगल पाण्डे को 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया जाये।८

पर बाद में यह तारीख 8 अप्रैल कर दी गयी, ताकि विद्रोह की आग अन्य रेजिमेण्टो में भी न फैल जाये। मंगल पाण्डे के प्रति लोगों में इतना सम्मान पैदा हो गया था कि बैरकपुर का कोई जल्लाद फाँसी देने को तैयार नहीं हुआ। नतीजन कलकत्ता से चार जल्लाद बुलाकर मंगल पाण्डे को 8 अप्रैल, 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पाण्डे को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जिस विद्रोह की चिंगारी को खत्म करना चाहा, वह तो फैल ही चुकी थी और देखते ही देखते इसने पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया।

इतिहास गवाह है कि मंगल पांडे द्वारा आरंभ की गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद ही 10 मई सन1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गयी। आधुनिक शोध पत्रों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 1857 की क्रांति का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में भले ही हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने लोकप्रिय विद्रोह का रूप धारण कर लिया। वस्तुतः इस क्रान्ति को भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पहली प्रत्यक्ष चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।

यह आंदोलन भले ही भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति न दिला पाया हो, लेकिन लोगों में आजादी का जज्बा जरूर पैदा कर गया। 1857 की इस क्रान्ति को कुछ इतिहासकारों ने महास्वप्न की शोकांतिका कहा है, पर इस गवीर्ले उपक्रम के फल स्वरूप ही भारत का नायाब मोती ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गया और जल्द ही कंपनी भंग हो गयी। 1857 के संग्राम की विशेषता यह भी है कि इससे उठे शंखनाद के बाद जंगे-आजादी 90 साल तक अनवरत चलती रही और भारत का अंततः स्वतंत्र देश के रूप में आविर्भाव हुआ।

(लेखक : स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी(सेवानिवृत्त)
तहबरपुर, पोस्ट -टीकापुर आजमगढ़,उ.प्र.)

संतोष तिवारी

पांडवानी लोककला की स्वर कोकिला : तीजनबाई

सदा के लिए सो गईं तीजनबाई
पंडवानी लोककला के स्वर्णिम अध्याय का अंत

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पंडवानी की अद्वितीय गायिका और पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का रविवार तड़के (05 जुलाई, 2026) रायपुर एम्स में निधन हो गया। 70 वर्षीय तीजन बाई ने सुबह करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही लोक कला का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया, जिसने महाभारत की कथाओं को अपनी बुलंद आवाज और अनूठी प्रस्तुति से दुनिया भर के मंचों तक पहुंचाया।

गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं तीजनबाई

एम्स के चिकित्सकों के अनुसार, तीजन बाई लंबे समय से उम्र संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन की खबर फैलते ही छत्तीसगढ़ और देशभर के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कला प्रेमियों ने इसे भारतीय लोक परंपरा की अपूरणीय क्षति बताया।

कापालिक शैली में पुरुषों को दी चुनौती

दुर्ग जिले के गनियारी गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचीं तीजन बाई ने उस दौर में पंडवानी गायन की परंपरा बदल दी, जब महिलाओं का खड़े होकर प्रस्तुति देना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता था।

उन्होंने पुरुष वर्चस्व को चुनौती देते हुए 'कापालिक शैली' को अपनाया और हाथ में तंबूरा लेकर महाभारत के पात्रों को जिस जीवंतता से मंच पर उतारा, उसने उन्हें लोक कला का वैश्विक चेहरा बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची लोककला

तीजन बाई ने इंदिरा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय

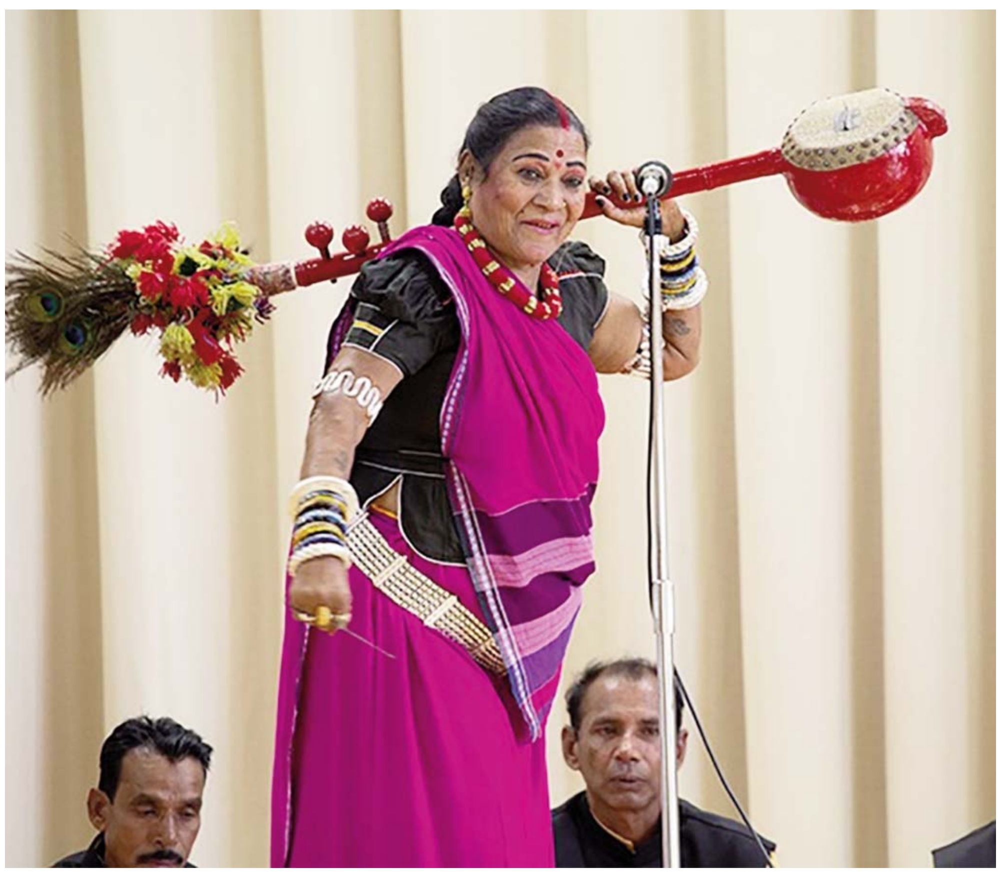

और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के सामने अपनी प्रस्तुति दी और भारतीय लोक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका कला पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनके निधन से भारतीय लोक संस्कृति ने अपनी सबसे बुलंद और प्रेरणादायी आवाज खो दी।

चन्द्र धर मिश्र

धर्म पिता

यह कहानी भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा पर आधारित है, जिसके माध्यम से उनके देशभक्ति के जज्बे को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह एक काल्पनिक कथा है, परंतु इस कथा का एक मात्र उद्देश्य देश के उन गौरवों का सम्मान करना है।

देश की प्रतिष्ठित चयन परीक्षा -एनडीए से चयनित और तीन साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने वाले नवयुवकों का आज कमीशन प्रोग्राम था।

जिसमें सेना के उच्च अधिकारी द्वारा ,सभी तीस होनहारों को लेफ्टिनेंट पद का नियुक्ति पत्र ससम्मान दिया जाना था।यह सेना की एक ऐसी प्रक्रिया है , जिससे नवनियुक्त सैन्य अधिकारी को न केवल एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने पर निभाई जाने जिम्मेदारी का अहसास हो, बल्कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने पर स्वयं पर गौरव करने का अहसास हो, अपनी विशिष्टता का अहसास हो।जो एक सैन्य अधिकारी के लिए बहुत आवश्यक है।

प्रोग्राम की आरम्भिक औपचारिकताओं के बाद , कार्यक्रम संचालक द्वारा नवनियुक्त सैन्य अधिकारियों को मंच पर बुलाये जाने की प्रक्रिया शुरू हुई -

मंच संचालक की गम्भीर आवाज गूंजी- सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा,एक ऐसे सैन्य अधिकारी को जिन्होंने न केवल एन डी ए की कठिनतम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया , बल्कि तीन साल की आर्मी ट्रेनिंग में भी उच्चतम अंक प्राप्त किए - वह है श्रीमान गौरव कुमार। कृपया आप मंच पर आयें और जब तक गौरव कुमार मंच पर आते हैं , मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना आवश्यक समझता हूं।गौरव कुमार के रग रग में वीरता समाई है।इनका वीरता का पारिवारिक इतिहास रहा है। इनके पिता शहीद ध्यान सिंह,वीर चक्र से सम्मानित हैं और लगभग सभी लोग उनसे परिचित हैं और उनकी वीरता के कायल हैं।र

पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

आगे की पंक्ति से छह फुट से भी अधिक लम्बाई का एक नवयुवक उठ खड़ा हुआ और लम्बे लम्बे कदमों से मंचं पर आ गया।

नवयुवक को आया देख,आज की सभा के मुख्य अतिथि,लेफ्टिनेंट जनरल वी के दत्ता अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उस नवयुवक से गर्मजोशी से हाथ मिलाया।

तभी एक युवती एक थाली में रोल किया हुआ नियुक्ति पत्र लेकर आगे बढ़ी।

वी के दत्ता ने नियुक्ति पत्र उस युवक के हाथों में थमाया। जिसे उस युवक ने अपने माथे से लगा लिया।इस तरह से वह अपने नये नये प्राप्त हुए सैन्य अधिकारी पद को सम्मान दे रहा था।

दत्ता जी ने हौले से युवक के कंधे को थपथपाया।

संचालक ने कहा,'सर आप इस युवक से कुछ कहना चाहेंगे ?

दत्ता कुछ कहने के लिए पोडियम की तरफ बढ़ने को हुए कि तभी एक सैनिक ने एक कार्डलेस माइक उनके हाथों में थमा दिया।

'नहीं, मुझे नहीं लगता,इस नवयुवक को कुछ भी समझाने की आवश्यकता है।जिसके खून में ही देशभक्ति के कीटाणु तैर रहे हो,उसको मैं क्या समझा सकता हूं? हां इतना जरूर कहूंगा कि एक शहीद वीर सैनिक का बेटा , अपने सभी साथियों में भी अपने जैसी ही भावना का संचार करेगा।रवी के दत्ता बोले थे।

हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा।

संचालक फिर से बोला,रमैं श्रीमान गौरव से अनुरोध करूंगा कि वह भी इस विलक्षण क्षण के अवसर पर अपने विचार रखें।र

दत्ता ने अपने हाथ में पकड़ा माइक युवक को पकड़ा दिया।

युवक ने बोलना शुरू,रसबसे पहले तो मैं यहां उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारियों से सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाये तो मुझे एक अज्ञानी बच्चा समझ कर क्षमा कर दें। मैं यहां सीखने आया हूं और मेरे अंदर की कमियों को सुधारने के लिए जो भी सीख मुझे दी जायेगी, मैं उसे हृदय से ग्रहण करूंगा।र

इतना कहकर वह युवक कुछ पल के लिए रूका।

पूरा हॉल खामोशी से उसकी बात सुन रहा था।

उसने आगे बोलना शुरू किया,रमेरे पिता शहीद सुबेदार ध्यान सिंह जिस दिन उस दुर्गम चोटी को फतेह करने में शहीद हो गये थे।उस समय मेरी उम्र सिर्फ दस साल थी। लेकिन मैं सबकुछ समझता था।उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि जिस तरह मेरे पिता ने देश रक्षा में अपनी जान बलिदान कर दी है,उसी तरह मैं सेना में भर्ती होकर देशकी रक्षा करूंगा और आवश्यकता हुई तो उन्हीं की तरह अपनी जान भी देश की खातिर कुर्बान कर दूंगा। आज मेरा वह सपना पूरा हो गया।'

पूरा हॉल तालियों की आवाज से फिर से गुंजायमान हो उठा।

जब तालियों की आवाज धीमी हुई तो गौरव ने फिर से आगे बोलना शुरू किया,रमुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाने में मेरे शहीद पिता की दिव्यात्मा की दुआओं के साथ, मेरी मां उमा देवी की जीवटता का भी बड़ा योगदान है। मेरी मां ज्यादा पढ़ी लिखी नही है लेकिन उनके अंदर देशप्रेम का ज्ञान भरपूर है।जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है कि देशप्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होगा।अगर कोई अन्य महिला होती, जिसका पति देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुका हो, अपने इकलौते बेटे को सेना में भेजने को बिल्कुल भी तैयार न होती लेकिन मेरी मां ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने न केवल मेरी सेना में जाने की इच्छा को स्वीकृति दी बल्कि

मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी।₹

इतना कहकर गौरव रूका और उसकी नजरें सामने बैठे जन समूह को देखने लगी , फिर एक व्यक्ति पर जाकर टिक गयी और फिर उसने आगे कहा,₹लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर एक व्यक्ति का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है।वह व्यक्ति जिसे मैं ससम्मान अपना धर्म पिता कह सकता हूं।अगर उनका सहयोग न मिलता तो मैं और मेरी मां कितना भी प्रयास कर लेते,शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता।वह आदरणीय व्यक्ति हैं रिटायर्ड कर्नल डी डी प्रसाद।

वह भी इस समय हॉल में उपस्थित हैं।मैं उनसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि कृपया वह मंच पर आकर मुझे सम्मानित करें।' वी के दत्ता ने गौरव के हाथ से माइक ले लिया,'अरे,कर्नल डी डी प्रसाद यहां उपस्थित हैं। मैं नहीं जानता था। वह मेरे अच्छे जानने वाले हैं।हम दोनों ने एक साथ ही आर्मी ज्वाइन की थी। प्लीज कर्नल प्रसाद,मंच पर आइये।'

भीड़ के बीच से एक करीब साठ वर्षीय व्यक्ति उठ खड़ा हुआ।वह भी गौरव की तरह ही लम्बा और स्वस्थ शरीर का व्यक्ति था।

भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ,वह व्यक्ति मंच तक आया।

गौरव तुरंत ही उनके कदमों में झुक गया।

रिटायर्ड कर्नल ने उस नवयुवक को उठाकर गले से लगा लिया।

कुछ देर तक दोनों गले से लगे रहे। दोनों की ही आंखें नम हो गयी थी।

दत्ता सर ने माइक रिटायर्ड कर्नल के साथ में पकड़ाते हुए कहा,'कर्नल आप भी इस लड़के के लिए कुछ बोलिए।'

प्रसाद ने अपनी नम हो गई आंखों को शर्ट की आस्तीन से पोछते हुए कहना शुरू किया,₹आज इस लड़के को मंच पर देखकर मेरे अंदर वही अहसास उत्पन्न हो रहा है , जैसा एक किसान को अपने द्वारा बोये गये बीज को एक परिपक्व वृक्ष के रूप में विकसित हुआ देखकर होता है।इस लड़के ने,न केवल अपने सपने को सच किया है, बल्कि मेरे सपने को भी सच कर दिया है।आज इसके शहीद पिता की आंखें भी खुशियों के आंसू बहा रही होगी।₹ इतना कहकर प्रसाद जी कुछ पल के लिए फिर से चुप हो गये ।उनकी आंखें पुनः नम हो गई थी।

उन्होंने फिर से अपनी आंखें पोंछी और दोबारा बोलना शुरू किया,₹इस मौके पर वह घटना याद आ रही है जिसने ध्यान सिंह को अमर कर दिया और मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी।

फिर वह पुरानी यादों में खोते चले गए।

देश में कारगिल का युद्ध चल रहा था। दुश्मन देश के सैनिकों ने देश की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर अवैध कब्जा जमा रखा था और उन चोटियों को मुक्त कराने के लिए ही यह कारगिल का युद्ध चल रहा था। वैसे तो इस अभियान में देश के वीर सैनिकों ने कई जगह पर फतेह हासिल कर ली। लेकिन एक महत्वपूर्ण चोटी अभी भी दुश्मन देश के कब्जे में थी। उस चोटी की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि दो बटालियन के सैनिक भी मिलकर,उस चोटी को खाली नहीं करा पा रहे थे। उस प्रयास में बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे।

तब सरकार ने राजपूत बटालियन को इस काम के नियुक्त किया।उस दल का नेतृत्व कर्नल डी डी प्रसाद कर रहे थे।वह जानते थे कि काम बहुत मुश्किल है और जिस रात को उन लोगों को अपने अभियान पर निकलना था, उससे कुछ देर पहले कर्नल ने अपने साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए सबको इकट्ठा करके समझाना शुरू किया।

वह बता रहे थे कि काम बहुत मुश्किल है और हमें पूरी सूझबूझ और ताकत से विरोधियों पर आक्रमण करना है और उन्हें वहां से खदेड़ देना है। निश्चित तौर पर उनके मन में योजना की सफलता को लेकर संशय था। तभी भीड़ से आवाज आई,'सर, निश्चिंत रहें।कल विजय हमारी होगी।कल मैं उस जीत हासिल करने के बाद आपसे उस चोटी पर ही मिलूंगा।' यह बात कहने वाले सुबेदार ध्यान सिंह थे।

ध्यान सिंह की इस विश्वास भरी बात ने जैसे सभी के मन में जमे संशय के बादलों को हटा दिया था और कर्नल सहित सभी लोग अगले दिन की विजय को लेकर आश्वस्त हो गये थे।

अगले दिन उस महत्वपूर्ण चोटी की विजय का अभियान शुरू हुआ।

युद्ध हुआ और उम्मीद से ज्यादा खतरनाक युद्ध हुआ। दुश्मन देश के बहुत से जवान मारे गये। अपनी तरफ के भी अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन अंत में विजय हमारी ही हुई। हमारे वीर सैनिक उस चोटी पर भारत का झंडा लहराने में कामयाब हुए लेकिन जब कर्नल उस चोटी पर पहुंचे तो सुबेदार अंतिम सांसें ले रहा था।

अपने अफसर को अपने निकट आया देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई,₹साहब, मैंने कहा आपसे कहा था कि अगले दिन चोटी पर मिलेंगे और देखिए मैंने चोटी जीत कर दे दी आपको।₹ और फिर उसकी आंखें सदा के बंद हो गईं।

कर्नल साहब वर्तमान में लौट आये थे,₹उस दिन मैंने चोटी तो जीत ली थी और बाद में हमारी सेना ने पूरा कारगिल भी जीता था लेकिन अपने साथियों की मौत ने मुझे बहुत व्याकुल किया। विशेष तौर पर सुबेदार की मौत ने। इस बात ने मुझे अंदर तक आंदोलित कर दिया कि जिस जवान ने मेरे एक आवाहन पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। एक पल को भी नहीं हिचका, उसके परिवार को अब बेसहारा तो नहीं छोड़ा जा सकता।अब मेरा फर्ज.है कि युद्ध में शहीद हुए परिवारों की देखभाल मैं करूं।'

'मैंने सेना से वी आर एस ले लिया। यद्यपि उस समय मेरी उम्र 45 साल थी और कई साल की नौकरी शेष थी।'

फिर एक और युद्ध शुरू हुआ। पैंतालीस परिवारों की सहायता करना आसान न था। उनके परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चे और सबसे बड़ी बात उन बेसहारा परिवारों को मोरल सपोर्ट देना। उन्हें कभी यह अहसास न होने देना कि वह बेसहारा है।कुछ सरकार से सहायता प्राप्त हुई,कुछ मैंने अपने प्रयासों से स्वयं सेवी संस्थाओ से अर्जित की , लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज इस लड़के को सेना का अधिकारी बना देख , मुझे लगता है, मैंने यह युद्ध भी जीत लिया है।₹ इतना कहते-कहते उनकी आवाज रूंध गई। उसने और बोला नहीं गया।

पूरा हॉल स्तब्ध था और दिल से उस सच्चे सैनिक को नमन कर रहा था।

इंडिया नहीं भारत

डॉ. मोतीलाल गुप्ता 'आदित्य'

भारत का उदय सिन्धु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। सिन्धु घाटी सभ्यता (पूर्व हड़प्पा काल 3300-2500 ईसा पूर्व, परिपक्व कालः 2600-1900 ई.पू. उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900-1300 ईसा पूर्व) की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घघ्घर/हकड़ा (प्राचीन सरस्वती) के किनारे हुआ। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यन्त विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं।

प्राचीन काल से ही इस देश का नाम भारतवर्ष रहा। आज भी सभी भारतीय भाषाओं में हमारे देश का नाम भारत ही है। भारतवर्ष को वैदिक काल से 'आर्यावर्त' 'जम्बूद्वीप' और 'अजनाभदेश' के नाम से भी पहचाना गया है। जम्बू द्वीप पृथ्वी के साथ द्वीपो में से एक है, जिन्हें हम वर्तमान में महाद्वीप कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रथम मनु स्वायंभुव के पुत्र प्रियव्रत थे उनके पुत्र आग्नीघ्र ने जम्बू द्वीप की खोज की थी और इसे अपने पुत्र जम्बू को दिया, जिनके नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हुआ। हमारी प्राचीन ग्रंथो के अनुसार धरती के साथ द्वीप थे इन सात दीपों में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक एवं पुष्कर का नाम आता है। जम्बूद्वीप इन सभी के मध्य स्थित है।

श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जम्बू दीप में नौ वर्ष (देश) थे, जिनके नाम है लीलाव्रत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरि वर्ष, केतुमाल वर्ष, राम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु

वर्ष, किलोक वर्ष और भारतवर्ष। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत वर्ष जंबूद्वीप का एक भाग है इसीलिए पूजा के समय पुजारी अक्सर स्थान के बारे में कहते हैं, 'जम्बूद्वीपे भरतखंडे।' जम्बू द्वीप के जिस भाग को आग्नीघ्र ने अपने पुत्र अजनाभ को दिया उसे अजनाभ वर्ष (देश) कहा गया। आगे चलकर अजनाभ के पुत्र और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष के स्थान पर भारतवर्ष हो गया। है। मार्कण्डेय पुराण में ऐसी वंशावली है, अजनाभवर्ष के पुत्र ऋषभदेव थे, जो स्वयंभू मनु की 5वीं पीढ़ी का क्रम जिन्हें वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप माना गया है, तथा जैन धर्म में उनको आदि तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। इन्हीं ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 'भरत' हुए। ये भरत ही भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। पुराणों के अनुसार सबसे प्रचलित धारणा यही है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट 'भरत' के नाम पर देश का नाम 'भारतवर्ष' पड़ा।

हिंदू पुराणो मे भी ऋषभदेव के पुत्र 'भरत' के नाम से देश का नामकरण 'भारत' स्वीकार किया गया। जिस भूभाग को अजनाभवर्ष और फिर भारतवर्ष कहा गया उसका क्षेत्र हिमालय से लेकर समुद्र तक था।

'उत्तरं यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम।

वर्ष तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः।।'

-विष्णु पुराण

इस श्लोक का अर्थ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे हिंदू पुराणों में भारत नाम का उल्लेख है।

सोभिचिन्त्याथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः।

ज्ञानवैराग्यमाश्रित्य जित्वेंद्रियमहोरगान।

हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्ष भरतस्य न्यवेदयत।

तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधाः।

-लिंग-पुराण (47.21.24)

अर्थात इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में स्थित राज्य भरत को दिया। तब से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया।

व्युत्पत्ति के अनुसार भारत (भा+रत) शब्द का मतलब है ज्ञान के प्रकाश में लीन। भारत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भा और रत। भा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश और रत अर्थात लीन। अतः भारत का अर्थ हुआ : वह भूमि जिसके निवासी ज्ञान की खोज में लगे हुए हों।

भारतवर्ष का नाम ऋग्वेद काल के चक्रवर्ती सम्राट भरत पर पड़ने की प्रामणिकताः 2000 वर्ष से भी अधिक पुरातन भारतीय इतिहास के धरोहर के रूप में संरक्षित, महाराज खारवेल के हाथी गुम्फाक शिलालेख (उड़िसा) में भी ऋषभदेव, उनके पुत्र 'भरत' और 'भारतवर्ष' के नाम का वर्णन उल्लिखित है। 'भारत वर्ष नामकरणः इतिहास और संस्कृति' नामक पुस्तक-लेखक, प्राध्यापक जिनेन्द्रकुमार भोमाज के अनुसार भारत शब्द की उत्पत्ति भरत के प्राकृत प्रयोग से हुई। नाभि के पुत्र ऋषभ, उनके अलौकिक पुत्र चक्रवर्ती सम्राट 'भरत' हुए। जो 14 रत्न, 32000 राजा और लाखों चतुरंग सेनाओं के स्वामी थे। जिसका उल्लेख भागवत, हरिवंश और आदिपर्व, विष्णु और ब्रह्मपुराण आदि में मिलता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय, सूरदास काव्य, डॉ.जायसवाल, डॉ. अवधरी लाल अवस्थी, डॉ.पी.सी.राय चौधरी, डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ.वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ.प्रेमसागर जैन, प्रो.आर.डी. कर्मरकर आदि ने भी ऋषभ के पुत्र 'भरत' के कारण देश को 'भारतवर्ष' के रूप में स्वीकार किया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ पुरातत्व विभाग के अनुसार ऋषभदेव की है।

'भारत' नाम के संबंध में ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है कि 'भारत' एक सम्प्रदाय अथवा जाति का नाम है। जो अपने गर्त में कई पीढ़ियों/ वंशजों को समाए हुए है। ऋग्वेद में भारत नाम का उल्लेख 79 बार हुआ है। वेदों में मिले उल्लेख के अनुसार 'भारत' सूर्य अर्थात सूर्यवंशी है और 'भारती' उसकी शोभा है। ईसा पूर्व 1150 में दशराज युद्ध आर्य और 'भारत' जातियों के बीच हुआ था। जिसमें 'भारतों' का नेतृत्व ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में यह वर्णन मिलता है कि महाभारत भारतीय परम्परा और संस्कृति का महाग्रंथ है। महाभारत शब्द के कथन का उल्लेख करते हुए महर्षि वेदव्यास जो कि

महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं, कहते हैं कि महाभारत में भारतवंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अनेक बार भारत, भरत सत्तम व भर्तर्षभ, अर्थात भरतवंशी तथा भरतश्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया गया है।

कुछ लोग भगवान श्रीराम के अनुज भरत के नाम से भी भारत नाम को जोड़कर देखते हैं। यह भी मान्यता है कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत (1500 ईसवी पूर्व से 1280 पूर्व के मध्य) व शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। उड़ीसा में उदयगिरि में गुफाओं में 2000 वर्ष से भी प्राचीन शिलालेखों में ऋषभ देव और उनके पुत्र भारत और भारतवर्ष का उल्लेख है। सभी वेदों में महाभारत, रामायण और सभी पुराणों में भारत नाम का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हजारों वर्षों से हमारे देश का नाम 'भारत' रहा है।

'इंडिया' नाम मूलतः सिंधु नदी से जुड़ा है। सिंधु भारत में उत्तर. पश्चिम की महान नदी का नाम सिंधु था। प्राचीन फारसी (ईरानी) लोग 'स' को 'ह' बोलते थे, इसलिए 'सिंधु' 'हिंदु' हो गया। इसी से 'हिंद' और 'हिंदुस्तान' शब्द बने। हिंदु इंडोस यूनानी इतिहासकारों और यात्रियों ने फारसी 'हिंदु' को 'इंडोस' के रूप में लिखा। 5वीं -4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोट्स और बाद में सिकंदर महान के अभियानों के समय यह नाम यूनानी संसार में प्रचलित हुआ। इंडोस इंडिया लैटिन भाषा में इंडोस से इंडिया बना। 550 ईसा पूर्व के आसपास पर्शिया (वर्तमान ईरान) के लोग भारत में आए तो सिंधु शब्द पश्चिम की ओर गया जो ग्रीक और लैटिन भाषा में इंडस के रूप में प्रयुक्त हुआ और वे भारत को इंडिया कहने लगे। रोमन ग्रंथों में 'इंडिया' शब्द मिलता है। बाद में यूरोपीय भाषाओं (अंग्रेजी आदि) में यही 'इंडिया' स्थिर हो गया। प्राचीन काल में यूनानी और रोमन व्यापारियों के माध्यम से 'इंडिया' नाम पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध था। वहां से यह नाम यूरोप पहुंचा और जब यूरोपीय देशों ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उन्होंने हमारे देश को भारत के बजाए इंडिया कहा। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने हमारे देश का अधिकारिक नाम इंडिया रख दिया।

कहा जाता है कि किसी देश पर शासन करने के लिए और उन पर मानसिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनके ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति और गैरवशाली नाम को मिटा कर निरर्थक या अपमानजनक नाम दिए जाएँ। इस संबंध में सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी कहते हैं, 'किसी व्यक्ति या देश का नाम बदलना प्रभुत्व स्थापित करने की तकनीक है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जब अंग्रेज अफ्रीकी देशों से लोगों को गुलाम बना कर लाए तो बंदरगाह पर सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले उनके नाम बदल दिए। उनके मूल नामों के स्थान पर कुकू, टोबु, नोनू जैसे निरर्थक नाम रख दिए गए और उनकी पहचान को मिटा दिया गया।' एक उदाहरण देकर वे कहते हैं, 'यदि मैं आपको पद्मनाभन कहता हूँ तो आप सीना तान कर खड़े होते हैं लेकिन जब आपको कुकू टोपू या इस प्रकार का कोई नाम दिया जाए तो आप अपने को बड़ा झुका हुआ सा पाते हैं।' उनके अनुसार ध्वनियों का मानव प्रणालियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिन्हें हमने मंत्र कहा। 'भारत' एक मंत्र है। 'भारत' शक्तिशाली है। वे कहते हैं, 'इंडिया' नाम हमें अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। कोई व्यक्ति या राष्ट्र यादों से, इतिहास और संस्कृति से बनता है। जब उसका नाम मिटता है तो

साथ ही वह भी मिट जाता है।'

जब यूरोपीय भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आए तो उन्होंने भारत को इंडिया तथा यहां के लोगों को 'इंडियन' कहा। कुछ समय पूर्व तक (17वीं से 19वीं शताब्दी तक) ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में 'इंडियन' शब्द का अर्थ अपराधी और अवैध संतान था। अर्थात 'इंडियन' शब्द एक गंदी गाली की तरह था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव और अज्ञानतावश हमने अपने गौरवशाली नाम के साथ निरर्थक नाम 'इंडिया' लगा लिया और भारतीय के लिए अपमानित करनेवाला शब्द 'इंडियन' अपना लिया।

भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के अनेक सदस्यों के विरोध के बावजूद हमारे देश के नाम में 'भारत' से पहले 'इंडिया' जोड़ दिया गया (भारत, यानी इंडिया)। अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखे जाने के कारण स्वतंत्रता के पश्चात अंग्रेजी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ 'भारत' शब्द का प्रयोग घटता गया और 'इंडिया' नाम बढ़ता गया। पूरे विश्व के साथ संपर्क में भारत के स्थान पर 'इंडिया' शब्द को ही प्रचलित किया गया। इस कारण विश्व में अधिकांश लोग 'भारत' नाम से परिचित नहीं रहे।

दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि स्वतंत्रता के पश्चात भी सरकारी नीतियों के कारण भारत में संविधान सम्मत भारतीय भाषाओं के स्थान पर शिक्षा और शासन में अंग्रेजी का प्रयोग व वर्चस्व बढ़ा और अंग्रेजी में हमारे देश का नाम 'इंडिया' लिखे जाने के कारण इंडिया नाम का प्रचलन बढ़ने के साथ-साथ भारत की नई पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास, ज्ञान-विज्ञान व संस्कृति को भी भूलती जा रही हैं। भारत में अंग्रेज 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के नाम से व्यापार करने आए थे बाद में इन्होंने 'भारत' पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 'इंडिया' शब्द को अपने अंग्रेजी शासन के साथ ही भारत में प्रचलित कर दिया। और स्वतंत्रता के पश्चात भी जिस प्रकार शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता गया, हजारों वर्ष से प्रचलित 'भारत' नाम पीछे छूटता जा रहा है और अज्ञानतावश 'इंडिया' नाम बढ़ता जा रहा है।

अनेक वर्षों से संसद विधानसभाओं और न्यायालयों में 'इंडिया' नाम हटाने की माँग होती रही है। 2020 में दिल्ली निवासी एक वकील नमः ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की थी, जिसके जरिए देश को अंग्रेजी में 'इंडिया' और हिंदी में 'भारत' का नाम दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्राचीन काल से ही देश को 'भारत' के नाम से जाना जाता रहा है। मगर अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से मिली आजादी के बाद अंग्रेजी में देश का नाम 'इंडिया' कर दिया गया देश के प्राचीन इतिहास को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने दलील दी थी कि 'इंडिया' नाम हटाने में सरकार की विफलता है और यह नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कहा गया कि वे इस मामले को भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें। 2010 और फिर 2012 में गोवा के एक कांग्रेस सांसद शांताराम नाईक द्वारा संसद में इस प्रकार का भी एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें इंडिया नाम को हटाने की माँग की गई थी। 2004 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव ने भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव उत्तरप्रदेश विधानसभा में पारित करवाया था। 2010 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने तथा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल नें भी 2023 में संसद में इस माँग को रखा था। सुप्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर जी तथा देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत नाम अपनाने और संविधान से इंडिया शब्द हटाने के लिए जनजागरण व प्रयास किए जाते रहे हैं।

2019 में 'वैश्विक 'हिंदी सम्मेलन' तथा 'जनता की आवाज फाउंडेशन' द्वारा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर इसके लिए धरना भी दिया गया, जिसके परिणम स्वरूप गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय द्वारा इस विषय पर पत्राचार भी हुआ। जब भारत में जी-20 सम्मेलन आयोजित किया गया तब पहली बार भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में भी भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री शब्दों का प्रयोग किया गया। तब विश्व में व्यापक स्तर पर भारत नाम प्रसारित हुआ। समय आ गया है कि हम गुलामी के प्रतीक 'इंडिया' नाम तथा इससे बने 'इंडियन' शब्द जो हमारे लिए गाली की तरह है उसे हटाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम आदरणीय मोहन भागवत जी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी सभी भाषाओं में इंडिया के बजाए भारत नाम अपनाने का आह्वान किया जाता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लालकिले की प्राचीर से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का आह्वान किया गया है। सरकार द्वारा अनेक जगह अंग्रेजी में भी इंडिया के बजाए भारत नाम का प्रयोग होने लगा है।

जब भारत में जी-20 सम्मेलन आयोजित हुआ था तो राष्ट्र प्रमुखों के लिए आयोजित रात्रिभोज के निमंत्रण-पत्र अंग्रेजी में भी भारत के राष्ट्रपति लिखा गया था। इसी प्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की नाम-पट्टिका पर भारत के प्रधानमंत्री गया था। भारत नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब देश के अनेक विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों ने अपने सभी प्रयोजनों के लिए इंडिया के स्थान पर सभी भाषाओं में भारत नाम अपनाने का निर्णय लिया है। दिन-प्रतिदिन यह संख्या बढ़ती जा रही है।

हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नाम पट्टिका पर भी अंग्रेजी में भारत लिखा गया था। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार भी धीरे-धीरे भारत की पराधीनता के प्रतीक 'इंडिया' नाम के बजाए 'भारत' नाम अपनाने की ओर अग्रसर है। जो भी हो इतना तो तय है कि अगर हमें अपने प्राचीन वैभवशाली गौरव, ज्ञान-विज्ञान की परंपरा के साथ अपनी अस्मिता की रक्षा के साथ आगे और विश्व की प्राचीनतम व उन्नत सभ्यता की अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना है तो भारत के उदय के लिए हमें 'इंडिया' नाम त्याग कर व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर संस्थाओं व संस्थानों आदि में 'भारत' नाम अपनाना होगा। राष्ट्रगान के अनुसार भारत ही है, 'भारत भाग्य विधाता'।

(लेखक : हिंदी विचारक, निदेशक, वैश्विक हिंदी सम्मेलन)

गौरी स्प्रैट दुल्हन बन चुकी हैं

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। गौरी आमिर खान की तीसरी पत्नी हैं। इसके पहले आमिर खान की लाइफ में किरण राव और रीना दत्ता रह चुकी हैं। गौरी से शादी के बीच आमिर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किरण राव के साथ नजर आ रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो दोनों साथ हैं। ऐसे में फैंस हैरान हैं कि नई नवेली शादी करके आमिर खान किरण राव के साथ ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कि काफी हैरान करने वाला है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। आमिर खान और किरण राव का ये वीडियो अभी का नहीं है। किसी ने शरारत करते हुए इस वीडियो को अभी का बताकर साझा किया है। जब किरण राव-आमिर खान की तलाक हुआ था और दोनों उस वक्त पानी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे थे।

सलमान खान का नाम लेने पर ऐश्वर्या ने करण जौहर को दिखाई आंख

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशन बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिलेशंस में से है। ब्रेक अप के बाद दोनों कभी एक दूसरे के साथ फिल्म में दिखाई दिए और ना तो कभी किसी इवेंट में ही साथ नजर आए। इतना ही नहीं सलमान खान और ऐश्वर्या रास दोनों में से किसी ने भी ब्रेक अप के बाद एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं की है। एक बार करण जौहर ने हिमाकत की कि वो ऐश्वर्या राय से सलमान के बारे में कुछ जिक्र करें तो इशारों इशारों में ऐश्वर्या में जिस अंदाज में करण जौहर की बोलती बंद की उससे फिर कभी कोई ऐश्वर्या के सामने सलमान खान का नाम लेने के बारे में भी सौ बार सोचेगा। दरअसल, सालों पहले जब ऐश्वर्या राय करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में पहुंची थी तो यहां करण जौहर में काफी घुमा फिर कर उनसे सलमान खान के नाम लेते हुए सवाल जवाब करने की कोशिश की।

सोनाक्षी सिन्हा ने घर में लगाई कलमा वाले गायत्री मंत्र की पेटिंग

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी काफी सुर्खियों में रहती हैं। शादी के बाद भी जहां दोनों अपने अपने धर्म मानते हैं तो वहीं एक दूसरे के धर्म की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। अब सोनाक्षी ने अपने घर में एक ऐसा बदलाव किया है जो नया ही ट्रेंड है लेकिन इससे लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है।सोनाक्षी सिन्हा ने अपने घर में 'गायत्री मंत्र और कलमा' के संगम वाली एक पेंटिंग लगाई है और इसके आगे जहीर के साथ फोटोशूट कराते हुए एक लंबा कैप्शन और तस्वीर के बारे में जानकारी दी है। तस्वीरें शेयर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, 'जब हमारी शादी हो रही थी और पंडित जी गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी अजान की आवाज हमारे घर तक पहुंची। उन दोनों प्रार्थनाओं की शक्ति ने ही हमारे घर को आज इतना खुशहाल बनाया है !' उन्होंने आगे कहा, 'एक दिन जब हम ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रहे थे, तो अचानक फोन आया। उन्होंने बताया कि वह हमारी शादी के लिए हमें एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वह क्या देना चाहती हैं, तो ऐसा लगा मानो उन्हें यह आइडिया हमारे दिलों से ही मिला हो। उन्होंने कहा कि पेंटिंग में हमारी दोनों तरह की मान्यताओं को दिखाया जाना चाहिए और यह भी कि कैसे वे प्यार और पॉजिटिविटी के तालमेल में बदल गई हैं।

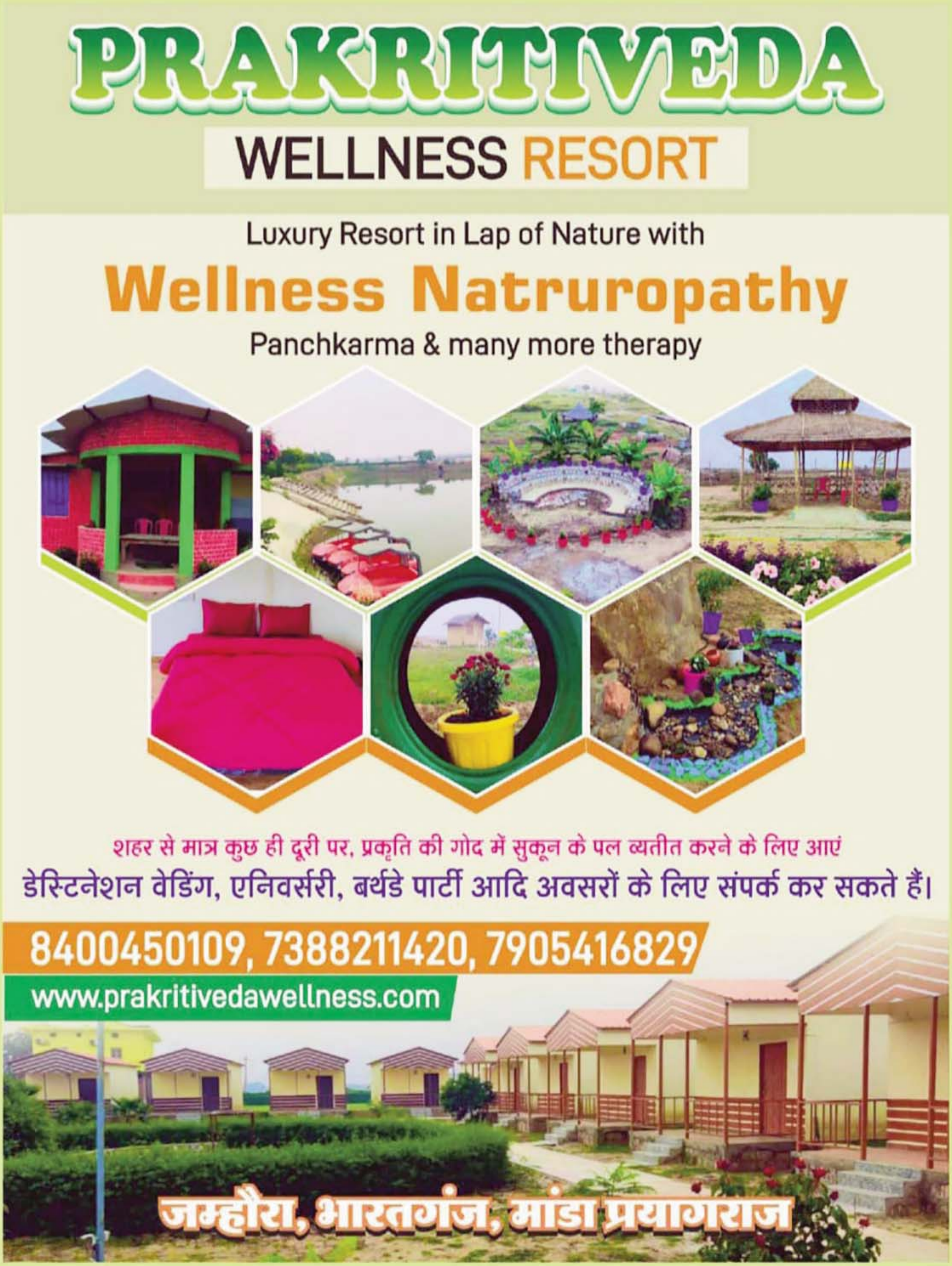
PRAKRITIVEDA
WELLNESS RESORT
Luxury Resort in Lap of Nature with
Wellness Natruropathy
Panchkarma & many more therapy
शहर से मात्र कुछ ही दूरी पर, प्रकृति की गोद में सुकून के पल व्यतीत करने के लिए आएं
डेस्टिनेशन वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी आदि अवसरों के लिए संपर्क कर सकते हैं।
8400450109, 7388211420, 7905416829
www.prakritivedawellness.com
जम्हौरा, भारतगंज, मांडा प्रयागराज

RNI No. : UPBIL/25/A0683